साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-28 अंक- 43 24 - 30 अक्तूबर 2021 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

महामारी से भी अधिक ख़तरनाक है बेरोज़गारी
पृष्ठ-6

न्याय कैसे मिल सकता है एक बड़ा सवाल?
पृष्ठ-7

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट

कितना सच बोलते हैं आंकड़े

अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट 2020 प्रकाशित हुई है, लेकिन यह एक कटु सत्य है कि आंकड़ों को लेकर हमारी रिपोर्टें आम तौर इतनी विरोधाभासी होती हैं कि देश की जनता को उन पर विश्वास करना कठिन हो जाता है।

आँकड़ों के बारे में आम सहमति है कि वे हमेशा या पूरा सच नहीं बताते और उनमें तैयार करने वालों की व्यक्तिगत पसंद-नापसंद की झलक हमेशा दिखती रहती है। पर यह भी सच है कि आंकड़ों का कोई विकल्प नहीं है, विशेषकर से भारत जैसे एक वैविध्यपूर्ण समाज में, जहां नीति-निर्धारकों के पास धर्मों, जातियों, भाषाओं और भिन्न राष्ट्रीयताओं में बंटे समाजों के लिए योजनाएं बनाते समय इनके अलावा कोई दूसरा बेहतर आधार न हो।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वर्ष 2020 की रिपोर्ट छपकर आ गई है। देश के विभिन्न राज्यों में अपराधों की स्थिति समझने के वास्ते किसी भी जिज्ञासु शोधार्थी के लिए ब्यूरो की रिपोर्टें एक प्रस्थान बिन्दु की तरह होती हैं। यह याद रखने की ज़रूरत है कि 1986 में स्थापित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का काम सिर्फ राज्यों से प्राप्त अपराधों के आंकड़े संकलित कर प्रकाशित कर देना है। उसमें इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है कि इनका समाजशास्त्रीय अध्ययन कर वह अपराधों के घटने या बढ़ने की प्रवृत्तियों की पहचान कर सके। इस काम को तो दूसरे शोध संस्थानों को ही करना होगा और निश्चित रूप से ब्यूरो संकलित आंकड़े उनके लिए बहुमूल्य सिद्ध होते हैं। आंकड़ों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचते समय यह ज़रूर याद रखना होगा कि सभी राज्य सरकारों की तरफ से कोशिश होती है कि अपराध को कम करके दिखाया जाए। अपवाद स्वरूप भी ऐसा राज्य तलाशना मुश्किल होगा, जो इन आंकड़ों के स्रोत पुलिस थानों में शत-प्रतिशत आपराधिक मामले दर्ज कराने पर ज़ोर देते हों। उत्तर प्रदेश जैसे राजयों में तो सर्वविदित है कि आधे से भी कम मामलों में एफआईआर दर्ज होती है।

बहरहाल, ब्यूरो की यह रिपोर्ट वर्ष 2020 की है, जब कोविड महामारी जब कोविड महामारी के चलते देश का अधिकांश हिस्सा बंद था। सड़कों पर कम लोग ही निकलते थे और ज़्यादातर कारखानों, दफ्तरों, या शिक्षा संस्थानों में ताले लटके हुए थे। ऐसे में, यह स्वाभाविक ही है किघरों के बाहर होने वाले अपराधों में गिरावट आई है और चारदीवारियों के भीतर घरेलू हिंसा या यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी होंगी। अवसादजन्य हिंसा या आत्महत्याओं में भी वृद्धि हुई ही होगी, पर लीग से हटकर सोचने की बौद्धिक सलाहियत से वंचित ब्यूरो ने अपराध के पारंपरिक खानों में इनके लिए गुंजाइश नहीं रखी है, इसलिए उन पर बातचीत नहीं हो सकती। इसके बावजूद इस रिपोर्ट से समकालीन समाज को समझने में मदद मिलेगी।

कोविड महामारी और परिणाम स्वरूप लॉकडाउन के चलते महिलाओं, बच्चों व वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराधों में कमी आई है, ऐसा ब्यूरो का मानना है, पर यह अन्य समाजशास्त्रीय स्रोतों के निष्कर्षों से भिन्न है। तमाम विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के ज़मीनी अध्ययन बताते हैं कि बड़े पैमाने पर रोज़गार जाने, आमदनी में कटौती और जीवन में तरह-तरह की अनिश्चितताओं से उत्पन्न तनाव ने मध्य आयु वर्ग के सदस्यों का जीवन एक ख़ास तरह के अवसाद से भर दिया है और यह घरेलू हिंसा के रूप में प्रकट हुआ है। बहुत से सर्वेक्षणों और अध्ययनों ने इसकी पुष्टि की है। ऐसे में, ब्यूरो के आंकड़े चौंकाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे विश्वसनीय हैं। इसी तरह से शिक्षा संस्थानों की बंदी के चलते घरों में कैद बच्चे भी चिड़चिडे हुए हैं और उनके व्यवहार में भी रेखांकित किया जा सकने वाला परिवर्तन आया होगा, जिनको पकड़ने में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े मदद नहीं करते। हालांकि, यह समझ में आता है कि चोरी, सेंधमारी, राहजनी, और डकैती जैसे मामलों में कोविड-काल में कमी आई है।

अनुसूचित जातियों के ख़िलाफ़ होने वाली ज़्यादतियों के मामलों में 9.4 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों द्वारा दर्ज मुक़दमों में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह समझ आने वाली स्थिति है, क्योंकि कोविड के लॉकडाउन से अमूमन ग्रामीण भारत, जहां अधिकतर अनुसूचित जातियां या जंगलों के नज़दीकी रिहायशी इलाके जहां अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, अप्रभावित रहे। इन इलाकों में जीवन चलता रहा, इसलिए इतनी वृद्धि सामान्य कही जाएगी।

लेकिन इन आंकड़ों में दो क्षेत्र दिलचस्प हैं। इस दौरान सरकारी आदेशों के उल्लंघ्रून के मामलों में वृद्धि हुई। यह स्वाभाविक ही है कि कोविड-काल के निर्देशों, यथा मास्क पहनने या सामाजिक दूरी बनाए रखने के आदेश का अनुपालन करना भारतीय जन के लिए सांस्कृतिक आघात की तरह था और इस संबंध में बड़ी संख्या में मुक़दमे कायम हुए। दूसरा क्षेत्र भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जहां अपराध कम हुए बताए गए। यह कैसे हुआ? नागरिकों के सामान्य संपर्क में आने वाले सरकारी कार्यालय आमतौर से बंद रहे, इसलिए स्वाभाविक रूप से संपर्क में कम नागरिक आए, और परिणामस्वरूप उनके उत्पीड़न की घटनाएं भी कम हुईं, लेकिन उस एक क्षेत्र का क्या हुआ, जिसका एक बड़ी आबादी से महामारी के दौरान पाला पड़ा। यह

बाक़ी पेज 11 पर

जार्डन के मशहूर रिसर्च संगठन की ताज़ा सूचि 2022 में

मौलाना महमूद मदनी भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूचि में प्रथम

संगठन ने मौलाना मदनी को मुस्लिम अधिकारों के लिए लड़ने वालों में नुमाया शख़्सियत बताया

नई दिल्ली : प्रसिद्ध शोध संगठन आर.आई.एस.एस.सी. ने अपनी हालिया सूचि 2022 जारी की है। जिस में जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रसिद्ध धार्मिक नेता मौलाना महमूद मदनी को लगातार तेरहवीं बार विश्व के 50 प्रभावशाली मुस्लिम हस्तियों में शुमार किया है। मौलाना मदनी इस सूचि में भारत के सबसे प्रभावशाली आलिम और धार्मिक नेता चुने गए हैं। वह भारत में प्रथम स्थान पर हैं, और पूरी दुनिया में 27वें नंबर पर रहे हैं। पांच सौ व्यक्तियों पर आधारित इस सूचि में दुनियाभर से अलग-अलग विभागों (राजनेता, सामाजिक, शिक्षा, स्कॉलरशिप, साइंस आदि) से संबंध रखने वाली कई शख़्सियात शामिल हैं, मगर टॉप में मौलाना अकेले ही भारतीय हैं। पिछले वर्ष मशहूर बरेवली आलिम मुफ़्ती अख़्तर रज़ा खां क़ादरी अजहरी इस सूचि में शामिल थे मगर वह वफात पा चुके हैं।

मौलाना महमूद मदनी दुनियाभर की इस फेहरिस्त में 27वें स्थान पर, जबकि भारत के लिए प्रथम स्थान हासिल करने वाले व्यक्ति बने। रिसर्च संस्था ने मौलाना महमूद मदनी की अज़ीम मिल्ली व समाजी ख़िदमात का ज़िक्र करते हुए लिखा है कि वह भारत में मुसलमानों के अधिकार के क्षेत्र में नुमाया रोल अदा कर रहे हैं, साथ ही आतंकवाद और उसको इस्लाम से जोड़ने का बड़ी बहादुरी से मुक़ाबला कर रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद से इस बारे में फतवा प्राप्त कर देशभर में आतंकवाद विरोधी कांफ्रेंसें कीं जिसका भारत के मुसलमानों पर अत्याधिक प्रभाव पड़ा। मौलाना महमूद मदनी ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रतिनिधि द्वारा दारुल उलूम देवबंद को आतंकवाद का केन्द्र कहने के बाद, पाकिस्तान को खुला पत्र लिखकर इसकी निन्दा की और इस बेतुके बयान का विश्व स्तर पर विरोधा किया। इसके अलावा वह मुस्लिम विद्वान्, धर्मस्थलों और धार्मिक व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए हर समय प्रयासरत रहते हैं। उनकी संस्था जमीयत उलेमा-ए-हिंद जो सौ वर्ष पहले स्थापित हुई है वह बीते समय से संगठित राष्ट्र की पक्षधर रही है। मौलाना महमूद मदनी ने राष्ट्रीय एकता के इस कल्पना को को ज़िन्दा रखा है और इस ताक़त के ज़रिए वतन में भाईचारा पैदा करने के लिए प्रयासरत है।

पाकिस्तान में आईएसआई चीफ फैज़ हमीद की छुट्टी

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की जबरिया सरकार बनवाने में मदद करने वाले पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ जनरल फैज़ हमीद को पद से हटा दिया गया है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, फैज़ पिछले महीने आर्मी चीफ जनरल क़मर बाजवा से मंज़ूरी लिए बिना काबुल गए थे। वहां तालिबान नेताओं के साथ सेरेना होटल में टी-पार्टी अटैंड की। सरकार बनाने में मदद की। फैज़ इमरान खान की पसंद थे और अगले साल आर्मी चीफ बनने वाले थे। बताया जाता है कि उनकी काबुल यात्रा से जनरल बाजवा और अमेरिका काफी नाराज़ थे। माना जा रहा है कि जनरल नदीम अंजुम आईएसआई के नए चीफ होंगे। जनरल हमीद को हटाए जाने की ख़बरें लंबे वक्त से गर्दिश कर रही थीं, लेकिन आर्मी की दबदबे के चलते पाकिस्तान का मैन मीडिया इन ख़बरों को दबा रहा था। हमीद को पेशावन कॉर्प्स कमांडर का चीफ बनाकर भेजा गया है।

आईएसआई चीफ की नियुक्ति का विशेषाधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है, यानि इमरान ने ही फैज़ को आइएसआइ चीफ बनाया था और उन्होंने ही हटा दिया। ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री आर्मी चीफ की सलाह पर यह फैसला लेता है। लिहाज़ा, यह कहा जा सकता है कि बजवा की सलाह पर ही जनरल हमीद को हटाया गया। हालांकि, इमरान किसी कीमत पर फैज़ को नहीं हटाना चाहते थे। पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट्स का मानना है कि इस मामले में अमेरिकी एंगल है। दरअसल फैज के काबुल दौरे और तालिबान नेताओं से मुलाक़ात बाइडेन प्रशासन को नागवान गुज़री। व्हाइट हाउस को ऐसा लग रहा था जैसे जनरल फैज़ तालिबान नेताओं के साथ मिलकर अफग़ानिस्तान में अमेरिकी शिकस्त का जश्न मना रहे हैं। ❑❑

कुलभूषण जाधव को मिली बड़ी राहत

पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने मौत की सज़ा पाए भारतीय क़ैदी कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कुलभूषण की वकील नियुक्ति करने के लिए भारत को और समय दिया है। सैन्य अदालत की ओर से जाधव को सुनाई गई सज़ा और दोषसिद्धि की उक्त अदालत समीक्षा करेगी। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्तिरी अधिकारी, 50 वर्षीय जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी एवं आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में दोषी ठहराते हुए मौत की सज़ा सुनाई थी। भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच न देने और मौत की सज़ा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अंतर्राष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) का रुख़ किया था। 'द हेग' स्थित आईसीजे ने जुलाई 2019 में फैसला दिया कि पाकिस्तान को जाधव को दोषी ठहराने और सज़ा सुनाने संबंधी फैसले को प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार करना चाहिए। साथ ही बिना किसी देर के भारत को जाधव के लिए राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने का भी अवसर दिया जाना चाहिए। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने जाधव के लिए वकील नामित करने के संबंध में कानून मंत्रालय के मामले की सुनवाई की। पीठ में मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनउल्लाह, न्यायमूर्ति आमेर फारूक और न्यायमूर्ति मियां गुल हसन औरंगज़ेब शामिल थे। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ख़ालिद जावेद ख़ान ने अदालत को याद दिलाया कि उसने पांच मई को एक आदेश पारित किया था जिसमें अधिकारियों से वकील की नियुक्ति के लिए भारत से संपर्क करने का एक और प्रयास करने को कहा गया था। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि संदेश भारत को दिया गया था लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ख़ान ने अदालत को यह भ बताया को यह भी बताया कि भारत एक अलग कमरे में जाधव तक राजनयिक पहुंच चाहता है, लेकिन अधिकारी उसे भारतीय प्रतिनिधियों के साथ अकेले छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते।

अफ़ग़ानिस्तान में कुपोषण से 10 लाख बच्चों को जान का ख़तरा

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने चेताया है कि इस वर्ष के अंत तक अफग़ानिस्तान में पांच वर्ष से कम आयु के 32 लाख बच्चे तीव्र कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। इन्हें यदि तत्काल उपचार नहीं मिला तो कम से कम दस लाख बच्चों के मरने का ख़तरा हो सकता है। देश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि हर्वे न्यूडोविक डी लिस और विश्व खाद्य कार्यक्रम की प्रतिनिधि व निदेशक मेरी एलेन मैकग्रॉर्टी ने यह चेतावनी जारी की है।

संयुक्त राष्ट्र के दोनों निकायों के उच्चाधिकारियों ने हेरात शहर की यात्रा के बाद कहा कि अफग़ानिस्तान में हालात बेहद ख़राब हैं। गंभीर खाद्य असुरक्षा देश में 14 लाख लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। इन लोगों को आर्थिक संकट के साथ भोजन, पानी और बुनियादी स्वास्थ्य व पोषण सेवाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के सर्वेक्षणों के मुताबिक, देश में 95 प्रतिशत परिवार पर्याप्त भोजन नहीं कर पा रहे है। वयस्कों की हालत यह है कि वे अपने बच्चों की ख़ातिर या तो भोजन छोड़ रहे हैं या ख़ुद कम खा रहे हैं। मैकग्रॉर्टी ने कहा कि यदि हमने अभी भी ऐसे मामलों में दख़ल नहीं दिया तो अफग़ानिस्तान में कुपोषण के हालात और भी गंभीर हो जाएंगे।

बहसतलब हो दिल्ली की बहुशासन प्रणाली

अगले वर्ष के शुरू में दिल्ली के तीनों निगमों के चुनाव होने वाले हैं। लगातार तीन बार से निगमों की सत्ता पर काबिज़ भाजपा को आम आदमी पार्टी (आप) इस आधार पर पराजित करने का प्रयास करेगी कि निगम में दूसरे दल के शासन से सरकार के काम में बाधा आ रही है। यही आरोप प्रत्यारोप दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार में शासन करने वाली पार्टियों के बीच लगता रहता है। भाजपा केन्द्र सरकार के बूते फिर से निगमों के चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के दिल्ली को 1993 में विधानसभा देने वाले कानून की व्याख्या करने के बाद केन्द्र सरकार ने संसद के पिछले सत्र में दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली का शासक बताने के लिए संविधान में संशोधन किया। दिल्ली को केन्द्र शासित प्रदेश रखते हुए दिल्ली को 1993 में विधानसभा दी गई थी। तब दिल्ली की आबादी एक करोड़ से कम थी, अब दो करोड़ से ज़्यादा है। दिल्ली में बहुशासन प्रणाली से राजनीति में कड़वाहट बढ़ी ही, पर स्तर पर केन्द्र की भाजपा की अगुआई वाली सरकार से दिल्ली सरकार और भाजपा शासित नगर निगम साथ काम कर पाए। आज़ादी के बाद से ज़रूरत और आबादी में बढ़ोत्तरी के चलते दिल्ली की शासन व्यवस्था में बार बार बदलाव होता रहा है। अब ज़रूरत है कि विस्तार से चर्चा करके कोई ठोस व्यवस्था बनाई जाए। दिल्ली सरकार की तरह दिल्ली के नगर निगम भी स्वशासी है। दिल्ली की 15 साल तक मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित को स्वशासित नगर निगम शुरू से ही खलता रहा। वे दिल्ली नगर निगम को उसी तरह से दिल्ली सरकार के अधीन वहां के निगम होते हैं। इस प्रयास में वे सफल नहीं हुई तो उन्होंने निगमों का पुनर्गठन के लिए समिति बनाई। पहले निगम की सीटें 138 से बढ़ाकर 272 की गईं, फिर उसे तीन हिस्सों में बांटा गया। दिल्ली के 87 प्रतिशत इलाकों में दिल्ली सरकार के समानांतर दिल्ली की नगर निगमों की सत्ता चलती है। दिल्ली में विधानसभा बनने से पहले निगम के पास ही दिल्ली की असली सत्ता थी, बाद में पहले बिजली, पानी फिर अगिनशमन, होमगार्ड, फिर सीवर, बड़ी सड़कें आदि अपने अध ीन करके दिल्ली सरकार ताक़तवर बनी। बावजूद इसके आज भी गृह कर, लाइसेंस, प्राथमिक स्वास्थ्य, समेत कुछ बड़े अस्पताल, प्राथमिक स्कूल, पार्क, पार्किंग आदि निगमों के अधीन हैं। तीन निगमों में से दो (पूर्वी और उत्तरी) अपने ख़र्चे का बोझ नहीं उठा पा रही हैं। इसलिए भी पैसे की लड़ाई आए दिन दिल्ली सरकार और निगमों में चलती रहती है।

दिल्ली सरकार का शहरी विकास सचिव निगमों की देख रेख करता है लेकिन दिल्ली की तीनों निगम सीध े केन्द्र सरकार के माध्यम से उपराज्यपाल के अधीन हैं। दिल्ली की साफ सफाई आदि के लिए दिल्ली के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार निगमों को पैसा देती है। दिल्ली सरकार कहती है कि उसे केन्द्र सरकार उसके हिस्से का पूरा पैसा नहीं देती और निगमों की शिकायत रहती है कि दिल्ली सरकार उसके हिस्से का पूरा पैसा नहीं देती। यह विवाद सड़कों पर भी आता रहता है। दिल्ली सरकार कहती है कि निगम में भ्रष्टाचार के चलते घाटा है, सरकार तो पूरा पैसा दे रही है। इसी तरह के कई और मुद्दे हैं जो बार-बार उठते रहे हैं। इसी तरह दिल्ली सरकार और मुद्दा भी तब से ज़्यादा उठ रहा है, तब से दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी काबिज हुई है। वे हर मुद्दे को दिल्ली का पूर्ण राज्य से जोड़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली को विध ानसभा देते समय जिस तरह से हर मुद्दे पर बहस होनी चाहिए थी वैसी हुई नहीं।

तभी तो अनेक सेवाएं विधान सभा ने प्रस्ताव करके निगम से लीं। पुलिस, ज़मीन और सेवाएं आरक्षित विषय होने से सरकार को दैनिक काम करने में कठिनाई होती है। दिल्ली देश की राजधानी है। देश की सरकार यहां से चलती है। दुनिया के हर देश के दूतावास दिल्ली में है। देशभर से लोग बेरोक टोक दिल्ली में आते हैं। दिल्ली किसी राज्य के अधीन न रहने से ही कोरोना काल में केन्द्र सरकार ने अर्द्धसैनिक बलों के बूते अस्पताल बनाने से लेकर सेना के अस्पताल को आम जन के लिए उपलब्ध करवाने के फैसले लिए।

दिल्ली की दूसरी समस्या यह है कि उसका इलाक़ा 1,483 वर्ग किलोमीटर से बढ़ने की भविष्य में कोई संभावना नहीं दिखती। आबादी बढ़ती जा रही है। इससे समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। इस बड़ी आबादी के चलते दिल्ली में अनाधिकृत निर्माणों की संख्या बढ़ती जा रही हे। अगर कारगर उपाय नहीं किए गए तो कुछ इलाक़ों को छोड़कर दिल्ली बस्ती बन जाएगी। इसलिए दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे पर बहस ज़रूरी है। या तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को जोड़कर दिल्ली को पूरी तरह से राज्य बना दिया जाए। अगर यह संभव न हो तो मौजूदा शासन व्यवस्था के लिए अधिकारों और ज़िम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा किया जाए।

वैसे तो दिल्ली में कई और सरकारी संस्थाएं स्वशासी हैं लेकिन नगर निगम, विधानसभा और केन्द्र सरकार यानि लोकसभा के सदस्यों को दिल्ली के मतदाता ही चुनते हैं। वही मतदाता यह समझ ही नहीं पाता है कि उसकी समस्या का समाधान किस शासन के पास है। अगर जनता से चुने हुए लोगों की सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं है तो उस सरकार की क्षमता पर प्रश्न उठते है। यह प्रश्न भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि अगर उपराज्यपाल ही शासक है तो चुनाव का मतलब कितना है। इस तरह के अनेक सवाल उठाए जाते रहे हैं दिल्ली के लिए एक शासन व्यवस्था बनाने की, जिससे दिल्ली देश की राजधानी रहते हुए दिल्ली के लोगों के लिए सही काम कर सके। ❑❑

संपादकीय

शांति मिशन

गाँधी की विरासत और हम

बीते 02 अक्तूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन एक बार पूरे भारत में मनाया गया था। आज़ाद भारत में जब बापू का जन्मदिन मनाते हैं तो यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि राष्ट्रपिता जिन सिद्धांतों को राजनीति में स्थापित करना चाहते थे उनकी स्थिति आज क्या है? बापू के स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हुए ही कई बार अपने अखबार 'हरिजन' में लेख लिख कर स्पष्ट किया था कि राजनीति में आने वाले व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन 24 घंटे जनता की जांच में रहना चाहिए वस्तुतः उन्हीं लोगों को राजनीति में आना चाहिए जिनका व्यक्तिगत जीवन भी सार्वजनिक हो। इसकी वजह साफ थी कि बापू राजनीति को कोई व्यवसाय या पेशा नहीं मानते थे बल्कि इसे जनसेवा या मिशन मानते थे। लोकतंत्र में वह सत्ता में बैठे लोगों को जनसेवक या सेवादार के रूप में प्रतिष्ठापित होते देखना चाहते थे। सदियों तक राजशाही में रहे भारत पर दो सौ सालों तक अंग्रेज़ों की सत्ता के दौरान आम भारतीयों में जो दास भाव (गुलाम प्रवृत्ति) जागृत हो गई थी उसे मिटाने के लिए बापू ने आज़ाद भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को इस वजह से प्रश्रय दिया जिससे आम नागरिक में ख़ुद ही अपनी सरकार का मालिक बनने का भाव जगे और उसमें भारतीय होने का स्वाभिमान पैदा हो।

लोकतांत्रिक प्रणाली में सामान्य नागरिक के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के सिद्धांत के साथ सत्ता में आये लोगों में नागरिकों की सेवा करने का भाव संवैधानिक ज़िम्मेदारी के रूप में निहित हो। भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें व्यक्तिगत सम्मान व निजी प्रतिष्ठा की कीमत पर कोई भी अधिकार किसी भी सरकार को नहीं दिया गया है। यह गांधीवाद की समूची मानवता को इतनी बड़ी सौग़ात है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है और जिसके आधार पर पूरी दुनिया में नागरिक स्वतंत्रता की मुहिम समय-समय पर तेज़ होती रही है। साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के ख़ात्मे में गांधी के इस सिद्धांत ने जो भूमिका निभाई उसका प्रमाण आज अफ्रीका समेत अन्य महाद्वीपों के वे देश हैं जिन्हें भारत की आज़ादी के बाद स्वतंत्रता मिली। गांधी केवल भारत में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पैरोकार थे। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने रंगभेद के ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ी थी उसका असर यह हुआ कि भारत में कांग्रेस के झंडे के नीचे स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करते हुए उनकी नज़र सबसे पहले यहां के दलितों पर पड़ी जिन्हें उन्होंने 'हरिजन' का नाम देकर समाम में उनकी हैसियत को बराबरी पर लाने का पहला क़दम उठाया और साथ ही यह भी घोषणा की कि छुआछूत को मिटाना भारत की आज़ादी के आंदोलन से किसी भी प्रकार कम नहीं है। यही वजह थी कि ज़िम्मेदारी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दी और इस हक़ीक़त के बावजूद दी कि स्वयं ब्रिटिश सरकार ने तब बहुत बड़े-बड़े अंग्रेज़ विद्वानों के नाम इस भूमिका के लिए सुझाये थे। गांधी को राष्ट्रपिता कहने कहने पर एक बार खासा विवाद भी खड़ा करने की कोशिश भी की गई थी मगर जिन लोगों ने विवाद खड़ा किया था वे भारत के इतिहास से अनभिज्ञ थे और यह नहीं जानते थे कि बापू को यह उपाधि सबसे पहले नेता सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद सरकार के उस रेडियो भाषण में दी थी जिसे उन्होंने भारतीयों के नाम प्रसारित किया था। महात्मा गांधी ने जीवन के हर पहलू में साधन और साध्य की शुचिता पर विशेष ज़ोर दिया और कहा कि साध्य तब तक पवित्रता नहीं पा सकता जब तक कि उसे पाने का साधन पूरी तरह साफ सुथरा न हो। इस सिद्धांत को उन्होंने राजनीति में जिस प्रकार उतारने की ताकीद की उससे लोकतंत्र में सत्ता पर कभी भी अयोग्य व्यक्तियों का अधि पत्य हो ही नहीं सकता।

भारतीय संविधान में चुनाव आयोग को स्वतंत्र व संवैधानिक संस्था बनाये जाने के पीछे यही सिद्धांत था। चुनाव आयोग को सीधे संविधान से ताक़त लेकर काम करने का अधिकार इसीलिए दिया गया जिससे वह कभी भी किसी भी राजनीतिक दल की सरकार के प्रभाव में न आ सके। चुनाव आयोग को लोकतंत्र की आधारभूमि इस प्रकार बनाया गया कि इस पर कार्यपालिका, न्यायपालिका व विधायिका की मज़बूत इमारतें खड़ी हो सकें। हम गांधी को आज उनकी जन्म जयंती पर याद करके औपचारिकता पूरी कर देते हैं मगर भूल जाते हैं कि जिन सिद्धांतों के लिए गांधी ने अपना बलिदान दिया उनकी आज किस सीमा तक दुर्गति हो रही है। कुछ नादान लोग गांधी को पाकिस्तान के हक़ में खड़ा हुआ दिखाने की नाकाम कोशिश भी करते हैं मगर भूल जाते हैं कि बापू ने पाकिस्तान के अस्तित्व को यह कहकर नकार दिया था कि 'मेरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु पाकिस्तान में हो' गांधी का यह कथन बताता हे कि वह पाकिस्तान के साथ भारतीयता का ही अंश समझते थे। इस 21वीं सदी के दौर में हम एक बार ज़रूर सोचें कि जिस रास्ते पर आज की राजनीति की भागमभाग हो रही हैं उसमें गांधी के विचारों का महत्व उस आम आदमी के संदर्भ में कितना है, जिसके एक वोट से सरकारें बनती बिगड़ती हैं। लोकतंत्र में उसके मालिकाना हक़ों को हमने कितना असरदार बनाया है?

तारीख़े इस्लाम

ख़ुतबाते सीरते तैयिबा

मुफ़्ती मुहम्मद सलमान मंसूरपुरी क़िस्त- 95

हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम शफ़ीउ़ल मुज़निबीन रहमतुल लिल आ़लमीन फ़रमायेंगे: मैं इस काम को अंजाम दुंगा, क्योंकि आप को कोई ख़तरा नहीं है, इस लिए कि क़ुरआन में ऐलान है: फ़तहे मक्का के साथ मुक़ामे लिवाये हम्द भी बयान कर दिया गया, इस आयत का जोड़ उस मुक़ाम से है, और अल्लाह तआ़ला का यह दस्तूर है कि उसके रास्ते में जो जितना सब्र करेगा उसको उतनी ही शरफ़त, बुलंदी और इ़ज़्ज़त अ़ता फ़रमायेंगे।(मुस्लिम शरीफ़ 1/110,111)

चुनान्चे पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, बैतुल्लाह शरीफ़ में हाज़िर हुए, ऐहराम नहीं था, इस लिए आप ने हजरे असवद का बोसा लिया, सवारी ही पर तवाफ़ फ़रमाया ताकि लोगों को पता चले और उसके बाद जिस ख़ानदान के लोगों के पास बैतुल्लाह शरीफ़ की चाबी रहती थी, वह चाबी मंगवा कर बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोल कर अंदर जो 360 बुत रखे हुए थे, आप के हाथ में एक छड़ी थी, उस से आप इशारा करते जाते थे, अगर पीठ की जानिब इशारा करते तो मुंह के बल गिरता और चेहरे की जानिब इशारा करते तो गुद्दी के बल गिर पड़ता, वह तमाम बुत वहाँ से साफ़ करा के अंदर तशरीफ़ ले गए, उसकी सफ़ाई की, उसके अंदर पुराने ज़माने से एक कबूतर बना हुआ रखा था, उसको तोड़ डाला, सफ़ाई करने के बाद जो सूरतें बनी हुई थीं, उन्हें मिटाया, फिर वहाँ पर नमाज़ वग़ैरह पढ़ीं, उसके बाद बाहर तशरीफ़ लाये। (ज़ादुल मआ़द मुकम्मल 676)

एक अ़ज़ीम ख़ुतबा

इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मक्का मुअ़ज़्ज़मा में फ़रोकश हुए (यानी क़याम फ़रमाया) तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बैतुल्लाह शरीफ़ के दरवाज़े पर खड़े होकर एक अज़ीम ख़ुतबा इर्शाद फ़रमाया, सब से पहले आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अल्लाह तआ़ला की हम्द व सना फ़रमाई। फिर ऐलान किया कि जाहिलियत की तमाम रसमें ख़त्म की जाती हैं और पुराने तमाम जानी व माली तनाज़आ़त (झगड़े, जो मक्का में आम थे) आज से फ़रामोश किए जाते हैं फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम क़ुरैश से इस तरह मुख़ातब हुए:

ऐ ख़ानवादा-ए-क़ुरैश! बेशक अल्लाह तआ़ला ने तुम से तुम्हारे जाहिलियत का ग़फ़ूरू और आबा व अजदाद पर एक दूसरे से बरतरी का सिलसिला मिटा दिया है। सब लोग आदम अ़लैहिस्सलाम की औलाद हैं और आदम अ़लैहिस्सलाम की पैदाइश मिट्टी से हुई है, फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह आयत तिलावत फ़रमाई: जिसका तर्जुमा यह है: (ऐ लोगो! हम ने तुम को एक मर्द और एक औ़रत (यानी हज़रत आदम व हव्वा अ़लैहिमुस्सलाम) से पैदा किया है, और तुम को मुख़्तलिफ़ क़ौमें और मुख़्तलिफ़ ख़ानदान बनाया ताकि एक दूसरे को पहचान सको, अल्लाह के नज़दीक तुम सब में बड़ा शरीफ़ वह है जो सब से ज़्यादा परहेज़गार हो। फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ऐ ख़ानदाने क़ुरैश! तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या बरताव करूंगा, सब हाज़िरीन ने कहा कि ''हमें आप से भलाई की उम्मीद है आप करीम इब्नुल करीम हैं'', तो आँ हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ऐलान फ़रमाया:

''जाओ! तुम सब आज़ाद हो।''

''अब तुम्हारे ऊपर कोई इलज़ाम नहीं है।

यह है पैग़म्बर-ए-इनसानियत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का उसवा-ए-मुबरका जिस की तारीख़ पेश करने से दुनिया-ऐ-इनसानियत आ़जिज़ है, इसी अज़ीम इनसानी बरताव की तालीम, इस्लाम अपने मानने वालों को देता है। (अर-रहीक़ुल मख़्तूम, 633)

इतने बड़े बड़े ज़ालिम व जाबिर और जानी दुश्मनों को पूरी क़ुव्वत हासिल होने के बाद में बख़्श देना और उन से इन्तिक़ाम न लेना, यह रहमते आ़लम ही का कारनामा हो सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। यह इस्लाम की तारीख़ और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का तर्ज़े अ़मल है, अल्लाह तआ़ला पूरी उम्मत और इनसानियत को इन अख़्लाक़ के अपनाने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये, हम सब को आफ़ियत से नवाज़े, पैग़म्बर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करना आसान फ़रमाये। (जारी)

नअ़त शरीफ़

दिलों के गुलशन महक रहे हैं ये क़ैफ़ क्यों आज आ रहे हैं
कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुज़ूर तशरीफ़ ला रहे हैं

कहां का मंसब कहां की दौलत क़सम ख़ुदा की ये है हक़ीक़त
जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीना को जो रहे हैं

हबीबे दावर ग़रीब परवर रसूले अकरम करम के पैकर
किसी को दर पर बुला रहे हैं किसी के ख़्वाबों में आ रहे हैं

न पास पी हो तो सूना सावन वो जिस पर राज़ी वही सुहागन
जिन्होंने थामा नबी का दामन उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं

नवाज़िशों पे नवाज़िशें हैं इनायतों पे इनायते हैं
नबी की नअ़तें सुना सुनाकर हम अपनी क़िस्मत जगा रहे हैं

बनेगा जाने का फिर बहाना कहेगा आकर कोई दीवाना
चलो नियाज़ी तुम्हीं मदीने, मदीने आक़ा बुला रहे हैं।

समाधान की मंशा के साथ आएं मंत्री तो ख़त्म हो सकता है आंदोलन

राकेश टिकैत

कृषि क्षेत्र में सुधार को लेकर संसद से पारित तीनों कृषि क़ानूनों के साथ एमएसपी और कुछ अन्य प्राविधानों का किसान संगठनों की ओर से लगातार विरोध हो रहा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ कई और जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठनों ने मोर्चा लगा रखा है। लगभग सालभर होने को है, लेकिन लखीमपुर खीरी में मध्यथता कर चुके भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत का मानना है कि किसान आंदोलन भी समाप्त हो सकता है, समझौते की राह निकल सकती है, लेकिन तब तक वार्ता करने मंत्री अधिकार के साथ आएं। वे इस मंशा के साथ आएं कि बैठकर रास्ता निकालना ही है। पेश है इन तमाम सवालों के जवाब राकेश टिकैत के साथ हुई एक वार्तालाप में।

प्रश्नः- सरकार कह रही है कि वह वार्ता के लिए तैयार है, किसान संगठन भी वार्ता के लिए तैयार हैं, तो अड़चन क्या है?

उत्तरः- देखिए, लखीमपुर खीरी में जब सरकार ने अपने अधिकारियों को पूरे अधिकार सौंपकर बातचीत के लिए आगे किया तो पांच छह घंटों में समस्या का समाधान निकल आया। हम वहां किसान परिवारों की मदद के लिए थे। हमारी नज़र इस पर थी कि कहीं कोई समस्या न खड़ी होने पाए। अधिकारी बातचीत से समस्या का समाधान करने की मंशा से आए थे। हमने पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत की बात की, जिससे फौरी हल निकाल लिया गया। जिस घर का 19 वर्ष का लड़का मरा हो, घर में उसकी दो बहनें और माता-पिता हों, आख़िर दरवाज़े पर कब तक लाश रखकर बैठे रहते। अधिकारी आए, उन्होंने सारी बात मानी और मामला निपट गया। अब तो मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी के लड़के पर कार्रवाई होनी है। केन्द्रीय मंत्री पर भी कई गंभीर आरोप हैं। उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी।

प्रश्नः- दिल्ली में भी तीन कृषि क़ानून के मामले का हल निकाला जा सकता है?

उत्तरः- (हैरानी भरे अंदाज़ में) सरकार चाहती तो समाधान कब का हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम तो समाधान चाहते हैं। हम खाप पंचायत से जुड़े लोग हैं। संघर्ष करते हैं, समाधान भी निकालते हैं। किसानों के मसले पर हम समाधान की ओर जाना चाहते हैं लेकिन सरकार हमें समाधान की बजाय संघर्ष की ओर खींच रही है

प्रश्नः- बातचीत के लिए आपकी ओर से कोई शर्त?

उत्तरः- देखिस, किसान तो समाधान की उम्मीद में यहां बैठे हैं। बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन यह बिना शर्त होनी चाहिए। इसके बिल्कुल उलट, सरकार कहती है कि कानून वापस नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ बात हो तो बताओ। भला ऐसे में कोई समाधान कैसे निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। हमने कभी यह नहीं कहा कि क़ानून वापस होंगे तभी हम बातचीत करेंगे। दरअसल, यह शर्त उनकी है कि क़ानून वापस नहीं होंगे। वो कहते हैं कि हमने अपना एजेंडा बता दिया है, इस पर बात कर लो। इसका मतलब तो यह हुआ कि 50 प्रतिशत तो वो सुरक्षित गए।

प्रश्नः- बातचीत होती है तो आपकी ओर से क्या कहा जाएगा?

उत्तरः- यह सरकार को बताया हुआ है। उन्हें अच्छे से पता है कि किसान क्या चाहते हैं। दरअसल इतने दौर की वार्ता में एक-एक बिंदु पर चर्चा हुई है, मगर समस्या यह है कि सरकार किसानों को कुछ देना ही नहीं चाहती। एमएसपी पर सरकार कानून बनाना नहीं चाहती। इसके अलावा बीज बिल है, प्रदूषण क़ानून है, बिजली संशोधन कानून है। बिजली और प्रदूषण पर मान गए थे। ट्रैक्टर की समस्या का समाधान करने की बात कह दी थी। हमने एमएसपी पर बात करने के लिए कहा तो कह दिया कि एमएसपी पर तब बात करेंगे जब तीनों कृषि क़ानूनों पर विस्तार से चर्चा हो जाएगी। ऐसे में बातचीत का क्या मतलब निकलेगा?

प्रश्नः- अगर किसी कारण बातचीत सफल नहीं हुई तब?

उत्तरः- (विस्मयपूर्ण मुस्कुराहट) एक बार राजस्थान में 12 साल सूखा पड़ा। किसान फसल बोते रहे, फसल बर्बाद होती रही, लेकिन न तो किसान ने अपना घर छोड़ा और न ही खेत। हम ऊपर वाले के आर्शीवाद से खेती करते हैं। कभी फसल होती है और कभी नहीं होती, लेकिन हम लगे रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि सरकार यह ग़लतफहमी निकाल दे कि हम थक जाएंगे या बिना समाधान लिए उठ जाएंगे। हम अपना हक़ लेकर रहेंगे, भले 12 साल लग जाएं।

प्रश्नः- क्या कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल आंदोलन का राजनीतिक लाभ ले रहे हैं?

उत्तरः- कांग्रेस क्या, देश का कोई भी राजनीतिक दल किसान आंदोलन का फायदा नहीं ले सकता। किसान को अच्छे से पता हे कि उसका हित कहां है और उसे क्या करना है?

प्रश्नः- गन्ने का मूल्य क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में अभी गन्ना मूल्य में वृद्धि हुई है?

उत्तरः- सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में जो कुछ कहा था अगर यदि उस पर शुरू से काम करती तो अब तक किसानों को मिल जाता। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधान सभा चुनाव होने है। तब सरकार को इसका ध्यान आया, मगर इससे बात नहीं बनेगी।

प्रश्नः- धान की कटाई चल रही है, आने वाले दिनों में रबी की बोआई होनी है। ऐसे में पराली जलाने की वारदातें होती हैं, जिससे दिल्ली के लोगों का सांस लेना दूभर हो जाता हे। क्या कहना चाहेंगे?

उत्तरः- (तंज़ करने का अंदाज़) यह कोई समस्या नहीं है जिसे लेकर हर बार शोर मचाया जाता है। यदि यह समस्या धान की पराली है तो सरकार के पास इतने बड़े अनुसंधान संस्थान हैं, जिसमें बड़े- बड़े कृषि विज्ञानी हैं। उन्हें तब तक फसल की ऐसी किस्म खोज निकालनी चाहिए थी जिसमें केवल दाने उगते। पत्ती और डंठल उगते ही नहीं। फिर तो पराली की कोई समस्या ही नहीं रहती। क्यों नहीं खोजा अब तक। विज्ञानियों का काम समस्या का समाधान तलाशना ही तो है। देश में हवाएं पुरवा, पछुआ और उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर को बहती हैं। हवाएं टेढ़े-मेड़े होकर नहीं बहतीं। तो फिर पंजाब से हवाएं दिल्ली कैसे आती हैं। मौसम के उतार चढ़ाव व अन्य वजहों की बात करने के बजाए किसान पर आरोप मढ़ते हैं यह ठीक नहीं है। ❑❑

हरियाणा और पंजाब गंभीर हो तो सुधरें प्रदूषण के हालात : गोपाल राय

मौसम में बदलाव के साथ ही दिल्ली-एनसीआर की हवा भी बदल गई है। करीब तीन माह से संतोषजनक श्रेणी में चल रही हवा कुछ दिन से मध्यम श्रेणी में आ गई है और खराब श्रेणी में पहुंचने को है। मौसम विभाग एवं सफल का पूर्वानुमान है कि जैसे-जैसे हवा में नमी बढ़ेगी, वायु प्रदूषण में भी इज़ाफा होता जाएगा। इसी के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने भी विंटर एक्शन प्लान लागू कर दिया है। इसके तहत प्रदूषण की रोकथाम के लिए 10 बिन्दुओं पर फोकस किया जा रहा है। प्रदूषण के मौजूदा हालात और इसकी रोकथाम को उठाए जाने वाले क़दमों पर पेश दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से हुई बातचीत के प्रमुख अंश :-

प्रश्नः- विंटर एक्शन प्लान के तहत कैसे होगी प्रदूषण की रोकथाम?

उत्तरः- इस प्लान के तहत 10 बिंदुओं पर फोकस किया गया है। प्रदूषण से जंग में दिल्ली के सभी विभाग मिलकर वायु प्रदूषण रोकने के लिए 75 और खुले में कूड़ा जलाने की घटनाओं पर नज़र रखने के लिए 250 टीमें गठित की गई हैं। एडवांस ग्रीन वार रूम और ग्रीन दिल्ली एप्प की शुरुआत किया गया है। 'एंटी डस्ट कैंपेन' शुरू किया गया है। निर्माण स्थलों पर धूल उड़ने से न रोकने वालों के ख़िलाफ़ चालान किए जा रहे हैं। सड़कों पर धूल उड़ने रोकने के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग यानि मशीनों से सफाई शुरू की जा रही है। सड़कों के गड्ढे भरे जा रहे हैं। सभी एजेंसियों को निर्देश दे दिए गए हैं। बड़े स्तर पर जगह-जगह एंटी स्मॉग गन लगाई जा रही है।

प्रश्नः- दिल्ली के प्रदूषण में पराली के रोल पर क्या कहेंगे?

उत्तरः- दिल्ली के प्रदूषण में पराली का बहुत बड़ा रोल है। गत वर्ष प्रदूषण में पराली के धुएं की 44 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी रही। बावजूद इसके पड़ोसी राजय इसकी रोकथाम के लिए बहुत गंभीर नज़र नहीं आते। अगर हरियाणा और पंजाब गंभीर हों तो प्रदूषण के हालात काफी हद तक सुधर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में पूसा बायो डिकंपोजर के घोल का छिड़काव करना चाहिए। हमने इसके सकारात्मक परिणामों की एक रिपोर्ट केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री और वायु गुणवत्ता आयोग को भी दी है।

प्रश्नः- क्या दिल्ली सरकार पराली के मसले पर कोर्ट का रुख़ कर सकती है?

उत्तरः- पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) सुप्रीम कोर्ट की ही समिति थी। लेकिन, पिछले वर्ष केन्द्र सरकार ने इसे खत्म कर केन्द्रीय वायु गुणवत्ता आयोग का गठन कर दिया। फिलहाल हम देख रहे हैं कि यह आयोग पराली की समस्या का क्या हल निकाल पाता है। पंजाब में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर हमारी सरकार बनी तो राज्य में पूसा बायो डिकंपोजर का निशुल्क छिड़काव कराया जाएगा और पराली जलाने की समस्या जड़ से ख़त्म की जाएगी।

प्रश्नः- पांच वर्ष पहले दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और अब में क्या फर्क देखते हैं?

उत्तरः- पिछले पांच साल में दिल्ली का वायु प्रदूषण 25 प्रतिशत तक कम हुआ है। आप सरकार स्थानीय प्रदूषण की रोकथाम को लेकर लगातार क़दम उठा रही है। 1.70 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी अधिसूचित की गई है और ई-वाहनों की खरीद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कनाट प्लेस में स्मॉग टॉवर लगाया गया है। आइआइटी कानपुर के साथ प्रदूषण के रियल टाइम स्रोतों की जानकारी पता लगाने के लिए एक अनुबंध किया गया है।

प्रश्नः- पिछले वर्ष प्रदूषण का जो हाल रहा था, इस वर्ष क्या स्थिति कुछ बेहतर होगी?

उत्तरः- हम लगातार प्रयासरत हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष हालात में और सुधार होगा। जल्द ही हम जन भागीदारी को बढ़ावा देने वाले कुछ अभियान भी शुरू करने वाले हैं। जल्द बायो डिकंपोजन का छिड़काव शुरू किया जाएगा। पता चला है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब सरकार भी इस साल इस तकनीक का सीमित स्तर पर उपयोग कर रही हैं।

प्रश्नः- दिल्ली के 150 हॉट स्पॉट के प्रदूषण से कैसे निपटा जाएगा?

उत्तरः- इन जगहों पर प्रदूषण के कारणों का पता लगाया गया है। इसके अनुसार ही सभी जगह प्रदूषण रोकने की अलग योजना बनाई गई है, जिसे लागू किया जा रहा है। ग्रीन वॉर रूम के ज़रिये भी इसकी निगरानी की जाएगी और प्रदूषण पैदा करने वाले स्रोतों को कम किया जाएगा। इसके लिए 21 सदस्यीय एक टीम भी बनाई

बाक़ी पेज 11 पर

पूरी पीढ़ी पर छा रहा है अंधेरा

पिछले कई दिनों से भारत में कोविड-19 के मामले प्रतिदिन 30 हजार से कम पर ठहरे हुए हैं। 05 राज्यों को कोरोना सूचि से निकाल दें तो कई सूबों में यह संक्रमण सैकड़ों में सिमटता नज़र आता है। यही वजह है कि उत्साही शोधार्थी ने दूसरी लहर की विदाई का उल्लास बिखेरना शुरू कर दिया है। इसी मुक़ाम पर एक प्रश्न भी सिर उठाता है क्या अब तीसरी लहर की आशंका से मुक्त होने का वक़्त आ गया है? इस मुद्दे पर जानकार एकमत नहीं है।

यह तय करना भी मुमकिन नहीं कि महामारी अब तक कैसा और कितना सामाजिक-आर्थिक क़हर ढा चुकी है, पर अब तक जो हुआ है, वह अपने आप में दारूण महागाथा है।

मिलिए सुमित्रा से! उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त जनपद में मज़दूरी करते समय एक दिन उनके मन में विचार कौंधा कि अगर यही हाल रहा तो मेरे बच्चे भी कुछ वर्ष बाद ऐसे ही दिहाड़ी पर देह खपाते नज़र आएंगे। घर लौटकर उसने अपने मन की यह बात पति को बताई। उसी रात दोनों ने निर्णय लिया हम दिल्ली जाएंगे। वहां मजूरी ज़्यादा मिलती है और दोनों बच्चों को पढ़ाने के संसाधन भी ज़्यादा है। अगले माह उन्होंने थोड़ा कर्ज़ लिया और नोएडा की ओर रवाना हो गए। नोएडा इसलिए, क्योंकि वहां उनके रिश्तेदार रहते हैं काफी जद्दोजहद के बाद वे वहां स्थापित हो गए। काम मिलने लगा था, बच्चे भी पढ़ने लगे थे कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया। वे दो माह तक बिना काम के डटे रहे, पर कब तक? उन लाखों लोगों की तरह वे भी दर बदल हुए, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उम्मीदों की झोली लेकर आए थे। अब उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा था। अपपने गांव में 'अपनों' की उपेक्षा ने उनकी गुरबत को और मारक बना दिया था। गांव में जैसे तैसे छह महीने काटे और फिर नोएडा लौट आए। इस दौरान बच्चे स्कूल न जा सके। जाते भी कैसे? स्कूलों ने भी दरवाज़े बंद कर रखे थे। पति-पत्नी को दोबारा काम मिल गया, पर दोनों नौनिहाल अब स्कूल जाने को तैयार नही। वे अकेले नहीं है, लाखों बच्चे ऐसे ही स्कूल जाने से कतराने लगे हैं।

चर्चित अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज, रीतिका खेड़ा और शोधार्थी विपुल पैकरा की टीम ने 15 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में सर्वेक्षण के दौरान पाया कि महामारी ने नौनिहालों की एक पूरी पीढ़ी को संकट में डाल दिया है। सर्वे के मुताबिक, सिर्फ आठ प्रतिशत ग्रामीण बच्चों ने नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठाया, जबकि 37 प्रतिशत ने कोई पढ़ाई नहीं की। क्या यह शैक्षिक रिक्ति कभी पूरी हो पाएगी? ऐसा हो पाना संभव नहीं। वजह? कोविड-19 के हमले से पहले जो बच्चा तीसरी कक्षा में था, वह तकनीकी तौर पर पांचवीं कक्षा में ज़रूर पहुंच गया है, मगर उसकी काबिलियत कक्षा एक के बच्चे के बराबर रह गई है। यह डरावना खुलासा है, क्योंकि ये बच्चे जब आने वाले सालों में आकदमिक काबिलयत के आधार पर आंके जाएंगे, तब उन्हें निराश होना पड़ेगा।

इस सर्वे में शामिल बच्चों में साठ प्रतिशत दलित और आदिवासी तबक़े से आते हैं। ज़ाहिर है, पहले से ही हाशिये पर पड़े इन समुदायों की अगली पीढ़ी को और अधिक असमानता का सामना करना पड़ेगा। केन्द्र सरकार के निर्देश पर तमाम राज्य सरकारों ने शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाएं देने का हुक्म ज़रूर सुना रखा था, पर इस आदेश का समूचा अनुपालन असंभव था। दूरदराज़ के गांवों में, जहां 4-जी की सेवाएं दुर्लभप हैं, यह दिक्क़त आम थी। आंकड़े बताते हैं कि देश के 77 प्रतिशत शहरी इलाक़ों तक स्मार्टफोन की पहुंच हो गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 51 प्रतिशत पर अटका हुआ है। स्मार्टफोन के अभाव में वर्चुअल कक्षा में भागीदारी नामुमकिन है।

प्रश्न उठता है कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है, उन्हें कितना फायदा पहुंचा? हाल ही में आए एक सर्वे में बताया गया है कि 'इंटरनेट क्रांति' से ऑनलाइन भुगतानों में दूसरी कोविड-वेब के दौरान ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा, ऑनलाइन कंटेंट के भी उपभोक्ता बेतहाशा बढ़े, जिनमें ऑडियो संगीत, समाचार, खेल सबसे आगे रहे, पर ऑनलाइन शिक्षा वैसे ही ठिठकी और सिमटी बनी रही। शिक्षा के पीछे रह जाने की एक वजह यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को स्मार्टफोन मुहैया कराने की हैसियत रखने वाले परिवार बहुत कम हैं। इस तरह के फोन पर पहला हक़ कुटुंब के मुखिया का होता है। आप इसे ऑनलाइन कंटेंट के उपयोग के आंकड़ों से भी समझ सकते हैं।

यही नहीं, गांवों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 14 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के 20 प्रतिशत बच्चे इस दौरान मिड-डे मील से वंचित रह गए। शोधकर्ताओं का मानना है कि इनमें से तमाम अब दोबारा स्कूल नहीं आ पाएंगे। विशेषज्ञ यह भी मानते है। कि बच्चों को हुए नुकसान की तत्काल भरपाई हनीं हुई, तो देश में आर्थिक असमानता की खाई और चौड़ी हो जाएगी।

यह आशंका तब और बलवती हो जाती है, जब हम रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। बैंक ने शेयर बाजार में सूचिबद्ध 2,500 से अधिक कंपनियों के विश्लेषण के दौरान पाया कि इनका मुनाफा इस आर्थिक वर्ष की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुक़ाबले तिगुना बढ़ गया है। मतलब साफ है, एक ओर कंपनियां मालामाल हुई है, वहीं आम आदमी पहले से अधिक बेहाल हो गया है। आश्चर्य नहीं कि गई जुलाई में सोना गिरवी रख कर्ज़ मांगने वालों की संख्या 77 प्रतिशत का भयंकर उछाल देखा गया। 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी (सीईएमआईई) के मुताबिक, अकेले अगस्त माह में 15 लाख लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। इनमें से 13 लाख ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। आप इन आंकड़ों को स्कूल से वंचित रह गए छात्रों से जोड़कर देखिए, तो आपको नई व्यथा-कथा काले अक्षरों में उभरती नज़र आएगी।

इतिहास गवाह है, महामारियां ऐसा ही सितम ढाती हैं। 1918 के स्पेनशि फ्लू ने एक करोड़ से ज़्यादा हिन्दुस्तानियों को निवाला बनाया था। उस समय अर्थव्यवस्था -10.5 प्रतिशत तक लुढ़क गई थी और महंगाई ने आसमान छू लिया था। उस दौरान जो मौतें हुई, उनमें समाज की निचली पायदान पर बैठे लोग ज़्यादा थे। 1919 में प्रकाशित एक ब्रिटिश रिपोर्ट ने बंबई (अब मुंबई) में हुई मौतों का

बाक़ी पेज 11 पर

धुआं है तो आग लगी होगी

कहावत है कि अगर कहीं धुआं दिख रहा हो आग ज़रूर लगी होगी। पिछले दिनों कर्नाटक की राजनीति ने भी कुछ ऐसा ही अहसास कराया। हुआ यूं कि सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चा तेज़ी से फैली कि भाजपा और कांग्रेस के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों - येदियुरप्पा और सिद्धारमैया के बीच गुपचुप मुलाक़ात हुई है। ख़बर ऐसे वक़्त में फैली जब कहा जा रहा है कि सीएम पद से हटाए जाने के बाद से येदियुरप्पा भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने की बात कह तो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नाराज़ हैं। पिछली बार भी उन्होंने आलाकमान के कहने पर मुख्यमंत्री पद तो छोड़ दिया था, लेकिन कुछ दिनों के अंदर अपनी अलग पार्टी बना ली थी। इस बार जैसे ही येदियुरप्पा और सिद्धारमैया ने तो यह चुनौते तक दे डाली कि अगर यह बात साबित हो जाती है कि येदियुरप्पा के साथ उनकी कोई मुलाक़ात नहीं हुई थी तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में मुलाक़ात को लेकर चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही। येदियुरप्पा और सिद्धारमैया की सफाई इतनी आसानी से लोगों के गले नहीं उतर रही है। उसी कहावत का ज़िक्र बार-बार हो रहा है कि अगर कहीं धुआं दिख रहा है तो आग ज़रूर लगी होगी। वैसे राजनीति में यह भी मुमकिन है कि मुलाकात की चर्चा 'नियोजित' हो। प्रेशर पॉलिटिक्स का यह भीा एक हिस्सा हो सकता है।

रोज़गार .....

सोशल वर्क
जॉब के साथ सटिस्फैक्शन भी

सोशल वर्क का मतलब अब सिर्फ ग़रीब तबक़े की मदद या अच्छे काम करना ही नहीं रह गया है, बल्कि यह एक कैरिअर ऑप्शन के रूप में भी सामने आयाा है। अगर आप भी समाज के प्रति जवाबदेही महसूस करते हों, तो सोशल सेक्टर को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

ऐसे होता है काम

आज जिस तरह से डिसेबिलिटी, ड्रग्स, मानसिक अवसाद, बुढ़ापा, बेरोज़गारी आदि की समस्या बढ़ रही है उसे देखते हुए समाजसेवा में युवाओं की काफी दरकार है। सोशल सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को लोगों की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक समस्याओं को जानना, समझना और फिर उसका हल निकालना होता है। इसे काउंसिलिंग, कांफ्रेंस, सेमिनार, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ज़रिए पूरा किया जाता है। इसके अलावा सोशल वर्कर ज़रूरतमंदों तक संसाधन भी पहुंचाते हैं।

स्किल्स जो हैं ज़रूरी

सोशल सेक्टर में काम करने के लिए आपके पास लोगों के साइकोलॉजिकल और इमोशनल पक्षों की समझ होनी चाहिए। आप में धैर्य और संवेदनशीलता होना बेहद ज़रूरी हैं इसके अलावा आप में सकारात्मक बदलाव और सही फैसले लेने की क्षमता भी होनी चाहिए।

डिग्री से बढ़ेगी समझ

वैसे तो समाजसेवा के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है लेकिन सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को तार्किक ढंग से समझने के लिए होम साईंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या सोशल साइंस में ग्रेजुएशन के बाद सोशल वेलफेयर, सोशल साइंस में मास्टर्स करना अच्छा रहेगा। इंडिया में कई इंस्टीटयूट्स और यूनिवर्सिटीज में इससे संबंधित कोर्स संचालित किए जाते हैं, जहां एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर दाख़िला मिलता है।

काम करने के अवसर

गांव-शहर की समस्याओं को लेकर बढ़ती जागरूकता, साक्षरता पर जोर एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति गंभीर नज़रिया विकसित होने से सेशल सेक्टर में काम करने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। ग्रामीण विकास विभाग, आशा, आंगनवाड़ी जैसी सरकारी एजेंसियों एनजीओ के अलावा इंडस्ट्रियल एवं कॉमर्शियल यूनिटस और कारपोरेट हाउसेज में सेशल साइंस प्रोफेशनल्स के लिए अनेक प्रकार के अवसर हैं। यही नहीं, यूनिसेफ, यूनेस्को, रेड क्रॉस, आक्सफैम जैसे इंटरनेशनल आर्गनाइजेशंस में भी इनकी अच्छी मांग है।

टॉप इंस्टीटयूटस

टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुम्बई। www.tiss.edu

दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली। www.du.ac.in

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। www.mgkvp.ac.in

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली। jmi.ac.in ❑❑

इस्लामी दुनिया

सबसे बड़ी मुश्किल में फंसा पाकिस्तान

इस्लामाबाद: पाकिस्तान सबसे बड़ी आर्थिक मुश्किल में फंस गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) से छह अरब डॉलर के कर्ज़ की उसकी आख़िरी उम्मीद भी टूट गई है। 11 दिन की वार्ता के बाद आईएमएफ ने कर्ज़ तो क्या एक अरब डॉलर की कर्ज़ की पहली किश्त देने से भी इंकार कर दिया हैं। अख़बार द एक्सप्रेट ट्रिब्यून अपपनी रिपोर्ट में कहता है कि वित्तमंत्री शौकत तारिक की टीम आईएमएफ को समझाने में विफल रही है।

हम बांग्लादेशी हिन्दुओं के साथ : इमाम एसोसिएशन

कोलकाता : पश्चिमी बंगाल में मुसलमानों के प्रतिनिधि संगठन बंगाल इमाम एसोसिएशन पिछले दिनों बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हुए हमले की निंदा की है और सभी से भारत एवं पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा रहने का आहवान किया हे। एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से जुड़े कम से कम 32,000 आयोजन किये गये हैं और सभी को सौहार्द और भाईचारे के साथ यह त्यौहार मनाना चाहिए।

एक ही परिवार के सात मरे

मुल्तान : पूर्वी पाकिस्तान में पिछले एक ही परिवार के सात सदस्यों की मौत आग लगने की वजह से हो गई। पुलिस इस घटना की तफ्तीश कर रही है। बचाव सेवा के प्रमुख डॉ. हुसैन मियां ने बताया कि पंजाब में मुज़फ्फर गढ़ जिले के अलीपुर इलाके में स्थित एक मकान में आग लगी। उन्होंने बताया कि दमकलकर्मियों ने 65 वर्षीय व्यक्ति, 35 और 19 वर्ष की दो महिलाओं तीन, 10 और 12 वर्ष के तीन लड़कों और दो महीने के शिशु का शव बरामद किया, घटना की जांच जारी है।

पाक नौसेना का दावा, भारतीय पनडुब्बी को अपने क्षेत्र में घुसने से रोका

इस्लामाबाद : पाकिस्तानी नौसेना ने पिछले दिनों यह दावा किया कि उसने अपने जलक्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रही एक भारतीय पनडुब्बी की पहचान कर उसका रास्ता रोक दिया। पाक नौसेना के द्वारा जारी बयान में कहा कि अरब सागर में हुई यह घटना बीते 16 अक्तूबर की है। यह इस तरह की तीसरी घटना है जब पाकिस्तानी नौसेना के निगरानी विमान ने भारतीय पनडुब्बी को पता लगाया है। पाकिस्तानी नौसेना द्वारा जारी वीडियो में एक पनडुब्बी दिखाई दे रही है, हालांकि भारतीय नौसेना की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

महामारी से भी अधिक ख़तरनाक है बेरोज़गारी

अजय शुक्ला

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के हथगाम में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति की मौत से सदमे में उसकी नवविवाहिता ने भी चार दिन बाद खुदकुशी कर ली। युवक मुंबई स्थित एक कंपनी में कार्यरत था। महामारी के दौर में नौकरी चले जाने से मानसिक संताप में था। दिल्ली में स्वर्णिम भविष्य का सपना संजोये बेरोज़गार इंजीनियर ज़रूरतें पूरी करने के लिए लुटेरा बन गया। बेरोज़गारी देश में जिस तेज़ी से बढ़ रही है, उसकी परिणति कमोबेश इसी तरह दिख रही है।

इन हालात पर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस के रूप में मनाया। पिछले कुछ सालों के दौरान नौकरियों में कटौती और ख़ाली पदों के न भरने की केन्द्र और राज्य सरकारों की नीतियों से हालात बदतर हो गये थे। अब कोरोना महामारी के दौर में, जब अर्थव्यवस्था का ढांचा भरभराया तो नौकरियों के साथ ही अन्य रोज़गार भी बर्बादी के हालात में पहुंच गये। नतीजतन, निजी क्षेत्रों में 40 प्रतिशत से अधिक नौकरियों में कटौती कर दी गई।

जो बचीं, उनमें वेतन-भत्तों में कटौती हो गई। सरकारी क्षेत्र में भर्तियां बेहद कम हुई और लंबे समय से ख़ाली पड़े लाखों पद या तो ख़त्म कर दिये गये या फिर उन्हें ठेके पर दे दिया गया। तमाम योग्य युवाओं की आयु सीमा ख़त्म हुई और वे अयोग्य हो गये। अब जो हालात बन रहे हैं, उनमें हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस समय भारतीय इतिहास में बेरोज़गारी सबसे अधिक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के शोध से पता चलता है कि इस साल जुलाई में जो बेरोज़गारी दर 6.95 प्रतिशत थी, वह अगस्त में बढ़कर 8.32 फीसदी हो गई। शोध में यह भी पता चला कि पिछले दिनों 10 लाख लोगों की नौकरियां गई थीं। कोरोना की दूसरी लहर अप्रैल के आसपास 70 लाख लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था। अगस्त माह में 15 लाख रोज़गार, पिछले माह के मुक़ाबले और कम हो गये। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है।

सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी ग्रामीण भारत में दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि महामारी और सरकारी नीतियों ने, बेरोज़गारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में शहरी बेरोज़गारी दर 9.78 फीसदी रही, जो जुलाई में 8.3 प्रतिशत थी। ग्रामीण बेरोज़गारी दर भी बढ़कर 7.64 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई में 6.34 प्रतिशत थी। नौकरी पेशा लोगों की तादाद लगातार घटी है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र में महामारी से डराया गया मगर सार्थक सरकारी समर्थन न मिलने से बाज़ार से नौकरियां खत्म होने लगीं। चौंकाने वाली बात यह है कि जहां रोज़गार दर गिरी है, वहीं श्रमिकों की संख्या में इज़ाफ़ा हुआ है। इस समय 3.6 स्किल्ड करोड़ लोग काम की तलाश में भटक रहे हैं।

सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी ग्रामीण भारत में दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि महामारी और सरकारी नीतियों ने, बेरोज़गारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में शहरी बेरोज़गारी दर 9.78 फीसदी रही, जो जुलाई में 8.3 प्रतिशत थी। ग्रामीण बेरोज़गारी दर भी बढ़कर 7.64 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई में 6.34 प्रतिशत थी। नौकरी पेशा लोगों की तादाद लगातार घटी है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र में महामारी से डराया गया मगर सार्थक सरकारी समर्थन न मिलने से बाज़ार से नौकरियां खत्म होने लगीं। चौंकाने वाली बात यह है कि जहां रोज़गार दर गिरी है, वहीं श्रमिकों की संख्या में इज़ाफ़ा हुआ है। इस समय 3.6 स्किल्ड करोड़ लोग काम की तलाश में भटक रहे हैं।

ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिलने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु के सामने दर्जनों चुनौतियां थी।। उन्होंने प्राथमिकताएं तय कीं और कहा कि हमें अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मज़बूती देनी होगी, जिससे समाज की आख़िरी पंक्ति में खड़े वयक्ति की आवाज भी सुनी जाये। हर व्यक्ति को भरपेट भोजन मिले। इसके लिए कृषि उत्पादन में हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। हर हाथ को रोज़गार मिलना चाहिए, जिसके लिए कुटीर उद्योगों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में भारी उद्योग और निगम स्थापित करना होगा। तकनीकी व्यवसायिक दक्षता में आत्मनिर्भरता बढ़नी चाहिए, जिसके लिए हमें उच्च शिक्षण संस्थान बनाने होंगे। लोगों को सेहतमंद रखने के लिए सस्ती अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खड़े करने होंगे। हमें किसी वाद में नहीं फंसना है, क्योंकि हमें सबको समान रूप से मज़बूत बनाना है।

हमें बाज़ारवाद में नहीं फंसना, इसके लिए उन्होंने मिश्रित 'सोशियो कैपिटल इकोनॉमी' पर काम किया। पूंजी जुटाने के लिए बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस के क्षेत्र में सरकार ने क़दम बढ़ाये। पंडित नेहरू ने ये सभी करने का संकल्प किया और कर दिखाया। यही कारण हे कि उनके दौर को राष्ट्र निर्माण का काल माना जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं ने देश को आत्मनिर्भर बनाकर हमें सशक्त किया। आज हमें, खाली खज़ाने के बाद भी कैसे आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा किया जाता है, यह पंडित नेहरु से सीखना चाहिए।

इस वक़्त देश में करीब 40 करोड़ बेरोज़गारों की फौज खड़ी है। हमारे यहां तीन तरह के बेरोज़गार हैं, पूर्ण बेरोज़गार, अर्द्ध बेरोज़गार और मौसमी बेरोज़गार। हमारी ढाई करोड़ बेटियां बेरोज़गार के रूप में अपने नाम दर्ज करा रही हैं। लगभग 12.5 करोड़ प्रवासी मज़दूर बेरोज़गार हो गये हैं। अनियोजित उद्योगों में काम करने वाले 67 प्रतिशत लोग बेरोज़गार होकर धक्के खा रहे हैं। आपको यह जानकर हैरत होगी कि ये हाल तब हैं, जबकि विभिन्न सरकारी विभागों में 80 लाख से अधिक पद ख़ाली पड़े हैं। सार्वजनिक उपक्रमों में छह लाख से अधिक लोगों के रोज़गार छिन गये हैं। बैंकों में 4.5 लाख लोगों की नौकरियां ख़त्म हो गई हैं सिर्फ केन्द्र सरकार सरकार में ही 10.25 प्रतिशत लाख स्वीकृत पद रिक्त हैं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय में 39 हज़ार पद ख़ाली पड़े हैं, तो प्रशासनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 42 हज़ार पद ख़ाली हैं, मगर इस पर राजनीतिक सत्ता बात नहीं करती है। आबादी के अनुपात में जो पद बढ़ने चाहिए थे, वह न बढ़ाकर संविदा और ठेके पर काम कराने की प्रथा सरकार ने बना ली है, जिससे कर्मचारी नहीं, गुलाम मिलें। देश में स्किल्ड डिग्रीधारी बेरोज़गारों की संख्या इस साढ़े तीन करोड़ से अधिक है। करीब सात करोड़ युवा रोज़गार दफ्तरों में बेरोज़गारों के रूप में दर्ज है। जिस तरह साल दर साल बेरोज़गारों की आबादी बढ़ रही है, उससे तय है कि चंद सालों में देश, बेरोज़गारों युवाओं का देश बन जाएगा। यही कारण है कि अब सरकार डिग्रियां लेकर चाय और पकौड़े बेच कर रोटी का जुगाड़ करने वाले को बेरोज़गार नहीं मानती है। 65 प्रतिशत डिग्रीधारी युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं। ऐसे ही करोड़ों युवा चंद रुपयों के लिए सियासी दलों के झंडे-डंडे लेकर टवीटर कैंपेन का हिस्सा बनने को मजबूर हैं। सरकार अपने प्रचार-प्रसार से लेकर तमाम कारपोरेट के लिए हज़ारों करोड़ खर्च करती है मगर सुरक्षित रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए नहीं सोचती है। हमारा युवा देश, इन हालातों के चलते बेरोज़गार भारत में तब्दील हो गया है।

दुख तब होता है, जब ये युवा और सरकार इस समस्या से लड़ने के बजाय हिन्दू-मुस्लिम, जाति, लिंग और क्षेत्र की से लड़ने में व्यस्त है। कुछ सियासी दलों को ये फायदेमंद लगता है, क्योंकि यह एक वोट बैंक बन जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि यही हालात रहे, तो चंद सालों बाद आपके बेटे-बेटियों का भविष्य अंधकार में होगा? वे क्या गुनाह करेंगे और क्यों न करें? इसका जवाब आपके पास भी नहीं होगा। सत्ताधारी दल अगर देश का हित चाहता है, तो उसको चाहिए कि वह सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों कपंनियों को बेचने के बजाय प्रोफेशनल्स के ज़रिए टॉरगेट बेस्ड चलाये। वह नये कल कारखाने और उपक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये।

कृषि उत्पादन आधारित उद्योग पंचायती व्यवस्था में स्थापित करें। पूंजीपतियों को भी प्रोत्साहित करें कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगायें। आबादी और सेवाओं के अनुरूप सरकार में नये पद सृजित किये जायें। आबादी नियंत्रण के साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक स्वायत्ता देकर सशक्त करें। अच्छी सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था हो। ग्रामीण न्याय व्यवस्था बने। जब इस नीति पर काम होगा, तभी हर हाथ को काम भी मिलेगा और सुख शांति भी।

न्याय कैसे मिल सकता है एक बड़ा सवाल?

लक्ष्मीकांता चावला

कुछ दिन पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने पंजाब सरकार को फटकारते हुए यह कहा था कि पंजाब में नशे के धंधे में फंसे छोटे लोगों को साधारण अपराध करने वालों को तो सरकार पकड़ती है, पद बड़े मगरमच्छ छोड़ दिए जाते हैं। इसी प्रकार भारत के सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जस्टिस रमन्ना ने भी एक विशेष आयोजन में भाषण करते हुए यह कहा है कि देश में पुलिस के हाथों मानवाधिकारों का सबसे ज़्यादा उल्लंघन/हनन हो रहा है।

उन्होंने यह भी कहा था कि पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री यातनाएं दी जाती हैं, जिससे कोई नहीं बचता और पुलिस हिरासत में मौतें भी चिंता का कारण है। देश का न्यायालय तो देखता भी, बोलता भी है और संवैधानिक सीमा में रहते हुए जनता को राहत देते हुए सरकारों पर अंकुश भी लगाता है। जैसे अभी अभी ट्रिब्यूनलों के अधिकारी नियुक्त न करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कड़ी टिप्पणी भी की गई, अपितु केन्द्र सरकार को यह भी कहा गया कि अगर केन्द्र ट्रिब्यूनलों के सभी पदों को नहीं भर्ता तो यह काम न्यायालय स्वयं भी कर सकता है। यह दुखद पर सच है कि आज न्यायपालिका के बिना कानूनी तंत्र से विधायिका से न्याय मिलने की आशा करना रेगिस्तान में पानी की खोज करने जैसा है। जो लोग अपने साधनों के बल से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं या उच्च न्यायालय तक ही गुहार लगा देते हैं तो उन्हें बहुत मात्रा में न्याय मिल जाता है, पर साधारण कानूनी प्रक्रिया में न्याय नहीं मिलता। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकारते हुए कहा है। माननीय जस्टिस के.एम. जोसफ और जस्टिस पी.एम. नरसिम्हा की पीठ ने कहा है कि अदालत किसी व्यक्ति को आरोपित महसूस होने का नोटिस भेजकर उसे तलब नहीं कर सकती। अदालत उसी व्यक्ति को अपने समक्ष पेश होने का बाध्यकारी आदेश भेज सकती है जिसके ख़िलाफ़ किसी अपराध में शामिल होने के ठोस सबूत हों। न्यायपीठ ने दंड प्रक्रिया की धारा 319 की जांच करते हुए कहा कि किसी भी अपराध की जांच या सुनवाई के दौरान अगर किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ ठोस सबूत मिलते हैं तो अदालत उसे सम्मन भेजकर उसकी उपस्थिति को आवश्यक बना सकती है। इस ताक़त का अनुचित प्रयोग नहीं किया जा सकता। इससे फिर सिद्ध हो जाता है कि बहुत से लोग पुलिस के जाल में फंसकर सालों तक जेल में या अदालती प्रक्रिया में पिसते रहते हैं। यह बहुत अच्छा है कि हमारे देश के न्यायाधीश, हमारी न्यायपालिका अब आम जनता की कठिनाईयों को मन से महसूस कर रही है, पर प्रश्न यह है कि क्या हर व्यक्ति शोषण और सरकारी तंत्र के अत्याचार का पीड़ित उच्च या सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच सकता है या हमारी सर्वोच्च अदालतें हर घटना का स्वत: संज्ञान ले सकती हैं। आज का सच तो यह कि कानून की छाननी से मोटे मोटे निकल जाते हैं और छोटे फंस जाते हैं। हज़ारों वर्ष पहले प्लेटो द्वारा कहा गया यह वाक्य आज भी सत्य है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि क़ानून के सामने सब बराबर हैं।

यह कटु सत्य है कि हमेशा साधारण अपराध करने वाला बड़ी सज़ा पाता है और बड़े-बड़े अपराध करने वाले अधिकतर सरकारी छननी से बड़े आराम से बाहर निकल जाते हैं। 17 सितंबर को एक साथ ही दो ऐसी घटनाएं हुईं जो इस सत्य की पुष्टि करती हैं। चंडीगढ़ में एक महिला सब इंस्पेक्टर दस हज़ार रुपया रिश्वत लेती पकड़ी गई। उसे थाने में बंद किया गया। अमृतसर में एक एएसआई बेचारा सिर्फ पांच हज़ार रुपये की रिश्वत ली और विजिलेंस की पकड़ में पहुंच गया। थानों और दफ्तरों में रिश्वत लेना आम बात है, पर सच्चाई यह है कि अधिकतर छोटी रक़म लेने वाले ही पकड़े जाते हैं, बड़े-बड़े सौदे तो थानों में नहीं, कहीं और किए जाते हैं और 17 सितंबर को ही रिश्वत सरकार द्वारा सरकारियों को दी गई। पंजाब के एक मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ के दामाद को एक्साइज विभाग का इंस्पेक्टर बना दिया गया। पांच और दस हजार रुपया रिश्वत लेने वाले निश्चित ही दंड के भागी होंगे।

यह कटु सत्य है कि हमेशा साधारण अपराध करने वाला बड़ी सज़ा पाता है और बड़े-बड़े अपराध करने वाले अधिकतर सरकारी छननी से बड़े आराम से बाहर निकल जाते हैं। 17 सितंबर को एक साथ ही दो ऐसी घटनाएं हुईं जो इस सत्य की पुष्टि करती हैं। चंडीगढ़ में एक महिला सब इंस्पेक्टर दस हज़ार रुपया रिश्वत लेती पकड़ी गई। उसे थाने में बंद किया गया। अमृतसर में एक एएसआई बेचारा सिर्फ पांच हज़ार रुपये की रिश्वत ली और विजिलेंस की पकड़ में पहुंच गया। थानों और दफ्तरों में रिश्वत लेना आम बात है, पर सच्चाई यह है कि अधिकतर छोटी रक़म लेने वाले ही पकड़े जाते हैं, बड़े-बड़े सौदे तो थानों में नहीं, कहीं और किए जाते हैं और 17 सितंबर को ही रिश्वत सरकार द्वारा सरकारियों को दी गई। पंजाब के एक मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ के दामाद को एक्साइज विभाग का इंस्पेक्टर बना दिया गया। पांच और दस हजार रुपया रिश्वत लेने वाले निश्चित ही दंड के भागी होंगे। होना भी चाहिए, पर जो राजनीतिक रिश्वत दी जाती है, वर्तमान सत्ता को बनाए रखने के लिए और भविष्य में सत्तापति बने रहने के लिए असंतुष्टों को संतुष्ट करने का जो रामबाण तरीक़ा है उसे अपनाते हुए ही पंजाब सरकार ने स्व. बेअंत सिंह जी के पोते, सांसद प्रताप सिंह बाजवा के बेटे, विधायक पांडे के बेटे और अब राजस्व मंत्री के दामाद को नौकरी दे दी है। यह ठीक है कि आलोचना से बचते हुए सांसद द्वारा बेटे के लिए नौकरी लेने से मना कर दिया गया, पर कैबिनेट ने तो स्वीकृति दे दी थी। मैंने यह बार-बार कहा कि जो कैबिनेट ऐसे अलोकतांत्रिक निर्णय लेती है या लालच अथवा भय से अनैतिक लाभ? देने का विरोध नहीं करती उसे धृतराष्ट्र की सभा कहना पड़ता है। धृतराष्ट्र की सभा में बहुत विद्वान सदस्य थे, पर राज भय या लालच से उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण तक का भी विरोध नहीं किया।

पंजाब मंत्रिपरिषद ने भी एकमत से मंत्री के करोड़पति दामाद को दया के आधार पर नौकरी देने की स्वीकृति दे दी। एक ज्वलंत प्रश्न यह भी है कि मानवाधिकारों का हनन अधिकतर पुलिस द्वारा ही तय किया जाता है। समय के लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए राजनेता भी इसमें बराबर के भागीदार हैं, क्योंकि आज पुलिस नेताओं के हाथ का खिलौना बनकर रह गई है। यह भी सच है कि किसी भी देश और समाज में पुलिस की आवश्यकता है। सरकारें अपना नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, अपराधियों पर नकेल पुलिस तंत्र के सहारे ही रखती है। अब आम आदमी कहां जाए। पुलिस सुरक्षा के लिए सेवा के लिए, कानून की हिफाज़त के लिए मानी जाती है, पर आज का सच यह है कि पुलिस आम जन के भय का कारण है। पुलिस का डंडा किसी भी छोटे बड़े पर बिना कारण बरस सकता है और सरकारी आदेश से भी लोगों का सिर तोड़ सकता है। जितना अनियंत्रित पुलिस तंत्र कोरोना काल में देखने को मिला उसने आतंकवाद के दिनों की याद करवा दी। आदेश तो सरकारी था कि कोरोना नियमों का पालन न करने वालों पर सख़्ती की जाए पर इस नियम पालन करवाने की आड़ में कितने लोगों के मानवाधिकारों का हनन हुआ। इसका सबसे काला और लोकतंत्र के मुंह पर चपत तूतीकोरम तमिलनाडु का उदाहरण भी है और देश के कई हिस्सों से मीडिया द्वारा दिखाया गया और कैसे डंडे बरसते हैं, उठक बैठक होती है। जुर्माने के साथ-साथ रिश्वत का दौर भी चला और कई बेकसूर क़ानून के ऐसे मकड़जाल में फंसा लिए गए जिन्हें निकलने में बहुत समय लगेगा। यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि पुलिस सरकार, समाज और देश के लिए ज़रूरी है, पर पुलिस के उद्दंड दंड को नियंत्रित कैसे रखा जाए यह सुरसा के मुंह जैसा प्रश्न है। सभी सरकारें पुलिस का दुरुपयोग करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा हो न्यायपालिका की तरह पुलिस कमिशन बनाया जाए और पुलिस नेताओं के हाथ की कठपुतली नहीं अपितु एक नियम में बंधी रहे। पुलिस की कठिनाईयों को भी यह कमीशन समझे। पुलिस की डयूटी के घंटे तय होने चाहिए। उनकी छुट्टियां सुरक्षित रखें। आज का ज्वलंत प्रश्न यह है कि क्या हिन्दुस्तान के लोगों के संरक्षण केवल न्याय पालिका से मिलेगा। अगर यह सच है तो फिर हर व्यक्ति न्यायपालिका के दरवाज़े पर पहुंचकर गुहार लगा सके। केवल धनपति ही उच्च न्यायालयों तक न पहुंचे, इसके लिए भी सरकारों से आशा नहीं, न्यायपालिका को ही व्यवस्था देनी होगी। सही तो यह है कि सरकारें पुलिस को न्यायपालिका की तरह ही कमीशन के अधीन करें।

ख़ास ख़बरें

चीन का हाइपरसोनिक न्यूक्लीयर परीक्षण

दुनिया में एक नए शीतयुद्ध ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही जंगी हथियारों की एक नई दौड़ फिर से शुरू होने का ख़तरा पैदा हो गया है। इस नए शीतयुद्ध की शुरूआत चीन ने नए हाइपरसोनिक न्यूक्लीयर मिसाइल के परीक्षण से की है। बाइडेन प्रशासन इस हथियार की मारक क्षमता से ज़्यादा इस बात से हतप्रभ है कि इसने यूएस के सबसे विश्वनीय समझे जाने वाले अर्ली मिसाइल डिफेंस बेस्ट सिस्टम को पूरी तरह चमका दे दिया। धरती की बहुत निचली कक्षा में चक्कर लगाने की वजह से चीन का यह परीक्षण पकड़ में नहीं आया।

उत्तर कोरिया ने समुद्र में किया बैलेस्टिक मिसाइल परीक्षण

सियोल : उत्तर कोरिया ने समुद्र में एक बैलेस्टिक मिसाइल दागी है, इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। इसे दक्षिण कोरियाई सेना ने पनडुब्बी से दागा जाने वाला हथियार बताया है। जापानी सेना ने भी मिसाइल परीक्षण की पुष्टि की है। यह मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय में हुआ जब कुछ घंटों पहले ही अमेरिका ने उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर कूटनीति बहाल करने की अपनी पेशकश दोहराई थी। अभी यह पता नहीं चला कि यह किस तरह की बैलेस्टिक मिसाइल थी या कितनी दूर गिरी।

कोरोना : चीन के दो उत्तरी क्षेत्रों में फिर लॉकडाउन

बीजिंग : चीन ने कोरोना वायरस के ख़ौफ में अपने दो उत्तरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लगा दिया है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने बताया कि नौ स्थानीय लोगों में वायरस मिला है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रशासन ने इन क्षेत्रों में जांच शुरू करने के साथ इनको पूरी तरह सील कर दिया है। हेल्थ कमीशन के अनुसार सौ नए मरीज़ में से पांच शांक्सी प्रांत में जबकि दो मामले चीन के क्षेत्र वाले इन मंगोलिया में मिले हैं।

दूषित खाने से परिवार के चार सदस्यों की मौत

बलरामपुर (यू0पी0) : जिले के शिवपुरा क्षेत्र में दूषित भोजन खाने से दो बच्चियों समेत एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गयी। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. सिंहल ने बताया कि शिवपुरा क्षेत्र के गोकुली गांव में भोजन करने के बाद कंचना (65), सुमन (30), रजनी (7) और शालिनी (03) को उल्टी दस्त शुरू हो गये।

इज्तमाई और इनफ़िरादी ज़िन्दगी में सब्र की अहमियत और इफादयत

मौलाना असरारुल हक़ कासमी

सब्र इस्लामी तालीमात व हिदायत का अहम हिस्सा है और एक वसी मफहूम को अपने दामन में समेटे हुये हैं लेकन सब्र का मतलब ये नहीं कि लोग नाकाम होकर या परेशानी में गिरफ्तार होकर हमेशा के लिये हालात से समझौता कर ले और अपने दिल में ये सोच ले कि वह सफल नहीं हो सकते बल्कि सब्र तो ये है कि अगर किसी मुआमला में किसी शख़्स को नाकामी का सामना करना पड़े तो वह भावुक न होकर सोच विचार करे और कारणों का पता लगाये अपनी कमियाँ तलाश करें और दोबारा संघर्ष करें। कई बार इंसान अपनी मंज़िल की ओर सफ़र करता रहता है मगर काफी वक़्त गुज़रने के बाद भी वह मंज़िल तक नहीं पहुंचता तो इसका ज़हन परेशान होने लगता है और मायूसी इसको घेर लेती है और वह ख़्याल करने लगता है कि वह अपनी मंज़िल को कभी नहीं पा सकता। ये वक़्त इसके लिये बहुत सब्र आज़मा होता है अगर वह सब्र करता है और मंज़िल की ओर अपने सफ़र को जारी रखता है तो एक न एक दिन मंज़िल पा जाता है और अगर सब्र छोड़ देता है और रास्ते से हट जाता है तो फिर कभी अपनी मंज़िल तक नहीं पहुंचता कई बार मंज़िल बहुत नज़दीक होती है।

आमतौर से देखा जाता है कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो वह बेक़ाबू हो जाता है और इस हालत में उल्टे सीधे फैसले लेता है कई बार गुस्से की हालत में लिये हुये फैसले इतने नुकसानदेह होते हैं कि लम्बे समय तक इस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती। ऐसी कितनी ही घटनायें आये दिन होती रहती हैं कि लोगों के बीच मामूली बात पर झगड़ा हुआ, दोनों को गुस्सा आया, गाली गलौच हुई मारपीट की नौबत आ गई, ऐसा नहीं होता है कि क़त्ल तक हो जाता है, इसके बाद लोग पछताते हैं क्योंकि एक की जान जाती है तो दूसरा जेल जाता है इनके ख़िलाफ़ मुक़दमात क़ायम होते हैं पैसे की बर्बादी होती है, बहुत से क़ातिलों को ज़मानत तक नहीं मिल पाती और कुछ को उम्र क़ैद हो जाती है और जेल के अंदर उनकी पूरी ज़िन्दगी कटती है। दुनिया से उसका सम्बन्ध ख़त्म हो जाता है। इनका सारा कैरिअर तबाह हो जाता है, अगर छूट भी जाता है तो मक़तूल के रिश्तेदारों के हाथों क़त्ल होने का डर बना रहता है, ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं कि लड़ाई के वक़्त सब्र से काम ले लिया जाता तो ये नौबत न आती इनकी ज़िन्दगी सकून से गुज़रती।

पति-पत्नी के बीच होने वाले विवादों में सब्र से काम लेना बहुत ज़रूरी होता है दोनों को चाहिये कि लड़ाई को आगे न बढ़ाये। पति को गुस्सा आये तो उसे चाहिये कि वह वहां से टल जाये। ऐसे मौक़े पर जो लोग सब्र करते हैं वह आने वाली मुसीबत से बच जाते हैं और पति पत्नी के बीच दो चार दिन में हालात फिर ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ

बहुत से लोग हालात का मुक़ाबला न करके आत्म हत्या कर बैठते हैं, जबकि दुनिया में ऐसी कितनी घटनायें हुई है कि लोगों को इतने कठिन हालात का सामना करना पड़ा कि उनको लगा कि इनकी ज़िन्दगी बेकार है लेकिन वह सब्र से काम लेते रहे और आख़िरकार उनके हालात अच्छे हो गये यानि सख़्त और निराशाजनक माहौल में भी सब्र से काम लेना चाहिये। कई बार मुश्किल के बाद आसानी आती है तंगी के बाद कुशीदगी पैदा कर दी जाती है।

लोग अपने गुस्से पर क़ाबू नहीं रख पाते और पत्नी की पिटाई कर देते हैं और जब पत्नी पुलिस में शिकायत करती है तो इनको सख़्त दिक्क़त का सामना करना पड़ता है। इस तरह कई बार मुस्तक़िल झगड़े के हालात बन जाते हैं, सकून जाता रहता है, कई पति झगड़े की सूरत में अपनी पत्नियों की तलाक दे देते हैं तीन तलाक या उससे भी ज़्यादा अब इनके बीच पति-पत्नि का सम्बन्ध ख़त्म हो जाता है और शौहर को जब होश आता है तो उसको पता चलता है कि उसकी ज़िन्दगी लुट चुकी है इसका घर तबाह हो चुका है और बच्चों का जीवन तबाह हो चुका है, ऐसे हालात में वह पछताता है अपने आप को कोसता है लेकिन जब तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आता। गुस्से में दी गई तलाक़ों ने पूरे-पूरे परिवारों को उजाड़ दिया है, इसलिये ऐसे अवसरों पर पत्नियों को भी ख़ामोश हो जाना चाहिये और पति को इतना गुस्सा न दिलाना चाहिये कि वह आपे से बाहर होकर कोई उल्टा सीधा क़दम उठा लें।

बहुत से लोग हालात का मुक़ाबला न करके आत्म हत्या कर बैठते हैं, जबकि दुनिया में ऐसी कितनी घटनायें हुई है कि लोगों को इतने कठिन हालात का सामना करना पड़ा कि उनको लगा कि इनकी ज़िन्दगी बेकार है लेकिन वह सब्र से काम लेते रहे और आख़िरकार उनके हालात अच्छे हो गये यानि सख़्त और निराशाजनक माहौल में भी सब्र से काम लेना चाहिये। कई बार मुश्किल के बाद आसानी आती है तंगी के बाद कुशीदगी पैदा कर दी जाती है। गुरबत के बाद मालदारी आती है, अल्लाह तआला ने फरमाया कि ''हर मुश्किल के साथ आसानी है, कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने ऊपर आने वाले हालात को बहुत ग़लत समझता है जबकि वह हालात आगे चल कर इसके लिये मुफीद साबित होते हैं और इनसे आसानी निकल आती है, जिससे इनका कैरिअर चमक जाता है, मिसाल के तौर पर कोई विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाता है तो वह इसको अपने लिये असफलता नहीं मानता बल्कि इसको अपने लिये चुनौती बना लेता है और अगली बार फिर पूरी तैयारी करता है इस तैयारी और मेहनत की वजह से अगले साल वह शानदार नम्बरों से पास होता है। अब इसके लिये आगे कोर्सों में दाख़िला आसान हो जाता है। मेहनत की वजह से इसकी जानकारी भी अच्छी हो जाती है, क्षमता भी पैदा हो जाती है और अच्छे नम्बरों की वजह से अच्छे कालेज में इसका दाख़िला आसान हो जाता है, फिर वह वक़्त के साथ तरक्क़ी करता चला जाता है और अच्छे भविष्य के बहुत से अवसर इसका स्वागत करने को तैयार रहते हैं, अगर वह फेल न होता या सेकंड डिवीजन पास होता तो उसको वक़्ती खुशी भले ही होती लेकिन बाद में इसके लिये आगे बढ़ने की संभावनायें इतनी न बनती। इसलिये हर व्यक्ति को मुश्किल हालात में या असफलता की सूरत में अपनी तैयारी मेहनत और लगन को और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिये और वक़्त का इंतज़ार करना चाहिये।

सब्र का तक़ाज़ा है कि मुश्किल हालात में भी इंसान साबित क़दम रहे। सही रास्ते से न हटे ग़लत तरीक़े न अपनाये। बहुत से लोग कठिनाई में सही रास्ते से हटकर गलत रास्ता अपना लेते हैं, आज हर कोई बहुत ज़्यादा दौलत हासिल करना चाहता है, इसके लिये वह कोशिश करता है, योजना बनाते हैं, उस पर अमल करते हैं लेकिन उनमें से कुछ असफल हो तो कुछ सफल। असफल लोगों में दो तरह के लोग होते हैं एक वह जो नाकामी के बाद भी सब्र करते हैं, दौलत न आने, तंगी की ज़िन्दगी गुज़ारने की स्थिति में भी सही और हलाल रास्तों को नहीं छोड़ते! दूसरे वह लोग होते हैं जो हलाल तरीक़े से ज़्यादा दौलत न जमा करने के बाद ग़लत और नाजायज़ रास्तों पर चल पड़ते हैं और हराम तरीकों से दौलत जमा करने में लग जाते हैं, यानि वह सब्र नहीं रख पाते। नाजायज़ और हरामतरी को अपना कर भले ही वह दौलत जमा करने में सफल हो जाये, इमारतें बना ले और ऐश की ज़िन्दगी गुज़ारने लगे मगर दरहक़ीकत ये इनकी असफलता होती है क्योंकि नाजायज़ और हराम काम करना गुनाह की बात है, फिर हराम रोज़ी के परिणाम ख़तरनाक होते है, इसके प्रभाव इसकी आने वाली नस्लों पर भी पड़ते हैं, मौत के बाद जब इसे हिसाब किताब से गुज़रना पड़ेगा तब इस पर क्या गुज़रेगी तसव्वुर किया जा सकता है।

नूरे क़ुरआन

(सूरा अल बैयना नं॰ 98)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

यह सूरा मदीना में उतरी इसमें आठ आयते हैं।

प्रारंभ करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो असीम कृपालु महादयालु है।

जो लोग अहले किताब और मुश्रिकों में से सच्चे दीन के इनकारी थे।

अहले किताब यहूद और नसारा हुए और मुश्रिकीन, वह क़ौमें हैं जो बुतों या आग वग़ैरह की पूजा करती थीं और कोई आसमानी किताब उनके हाथ में न थी।

वे (अपने इंकार से) हटने वाले न थे जब तक कि उनके पास खुली दलील न आ जाती (अर्थात्) एक अल्लाह का रसूल जो पाक ऐसे पृष्ठ पढ़कर सुना दे।

हज़रत मुहम्मद सल्ल॰ के रसूल होने से पहले तमाम धर्मों वाले बिगड़ चुके थे और प्रत्येक अपनी ग़लती पर घमंड करता था। अब चाहिए कि ये लोग किसी तत्वज्ञानी या ऋषि या न्यायप्रिय बादशाह के समझाने से सीधी राह पर आ जायें तो यह भी संभव न था। जब तक कोई ऐसा महान रसूल न आये जिसके हाथ अल्लाह की पाक किताब इसकी शक्तिशाली सहायक न हो जो कुछ सालों में ही एक-एक मुल्क को ईमान की रोशनी से भर दे और अपनी महान शिक्षा हिम्मत और दृढ़ निश्चय से दुनिया की काया पलट कर दे, फलस्वरूप वह रसूल अल्लाह की किताब पढ़ताह हुआ आया जो पवित्र पृष्ठों में लिखी हुई है।

जिनमें सुदृढ़ विषय लिखे हैं।

अर्थात् इसके विषय बिल्कुल सच्चे सुदृढ़ और मध्यम दर्जे के हैं या इस आयत का अर्थ 'सुदृढ़ किताबों' से लिया जाये अर्थात् कुरआन की प्रत्येक सूरत गोया पूर्ण किताब है, या यह मतलब हो कि जो अच्छी पुस्तकें पहले आ चुकी हैं उन सबके आवश्यक सारांश इस पुस्तक में लिख दिये गये हैं।

और वे जो अहले किताब थे वे इस खुली दलील आने के पश्चात् ही विभिन्न हो गये।

अर्थात् इस रसूल और उस किताब के आने के पश्चात् शंका नहीं रही अब अहले किताब हठ से विरोधी हैं, शंका से नहीं। इसीलिए उनमें दो वर्ग बन गये हैं जिसने हठ की वह अवज्ञाकारी रहा, जिसने इंसाफ़ किया वह ईमान ले आया। चाहिए तो यह था कि जिस अन्तिम रसूल की प्रतीक्षा कर रहे थे उसके आने पर अपने विरोधों को समाप्त करके सब एक रास्ता पकड़ लेते मगर उन्होंने अपने अभागेपन और शत्रुता से अपनी एकता के कारण अपनी भिन्नता और आपसी विरोध का कारण बना लिया। जब अहले किताब की यह दशा है तो अज्ञानी मुश्रिकों का तो पूछना ही क्या?

चेतावनी :-ह शाह अब्दुल अज़ीज़ ने 'यहां खुली दलील' से तात्पर्य हज़रत मसीह अलै. को लिया अर्थात् जब हज़रत मसीह खुले-खुले निशान लेकर आये तो यहूद दुश्मन हो गये और ईसाइयों ने भी सांसारिक लालच में फंस कर अपने संघ और पार्टियां बना ली। मतलब यह है कि रसूल का आना और किताब का उतरना अल्लाह की तौफीक़ (सामर्थ्य) के बिना लाभ नहीं करता, कितने ही सामान हिदायत के जमा (इकट्ठे) हो जायें जिनको अल्लाह की ओर से तौफीक़ (सामर्थ्य) नहीं मिलता वह उसी प्रकार टोटे में पड़े रहते हैं।

हमारी क़ौम और देश का फायदा शिक्षा में ही है

सर सैयद अहमद ख़ान

सर सैयद अहमद ख़ान साहब एक प्रसिद्ध मुस्लिम धर्म सुधारक, शिक्षक और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म एक मज़बूत मुग़ल संबंधित परिवार में हुआ। उन्होंने पारंपरिक शिक्षा के साथ कुरआन, फारसी, अरबी, गणित और चिकित्सा शिक्षा का भी अध्ययन किया। अपने पिता के मृत्यु के बाद वे ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में शामिल हो गए और धीरे-धीरे पदोन्नति करके निचली उन्हें निचली अदालतों का न्यायाधीश बना दिया गया। उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की और उनमें से मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम विकसित हुआ विशेष है।

सर सैयद अहमद ख़ान साहब (17-10-1827-27-03-1898) ऐसे शिक्षक और नेता थे जिन्होंने भारत में मुसलमानों के लिए आधुनिक पढ़ाई की शुरुआत की। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की।

यहां हम पेश कर रहे हैं वर्ष 1887 में लखनऊ में उनके दिए भाषण के प्रमुख अंश :-

मुझे राजनीति पर बोलने का अधिकार नहीं है और मुझे याद नहीं कि इससे पहले मैंने कभी कोई राजनीतिक भाषण दिया हो। मेरा ध्यान हमेशा अपने मुसलमान भाईयों की शिक्षा की ओर रहा है क्योंकि शिक्षा से ही मैं अपने लोगों, हिन्दुस्तान और सरकार के बहुत फायदे की उम्मीद करता हूं। इस भाषण का मक़सद उस नज़रिये की बात करना है जो राजनीतिक आंदोलन के बारे में मुस्लिम क़ौम को अपनाना चाहिए। मैं कोई दार्शनिक प्रवचन नहीं दे रहा। न ही राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं। मैं यह चर्चा करूंगा कि यह आंदोलन देश और इसमें रहने वाली दूसरी क़ौमों के लिए काम का है या नहीं। अगर यह देश या हमारे लिए ख़तरनाक है तो हमें अलग रहना चाहिए।

सबसे पहले मैं सरकार द्वारा अपनाए गए शासन के तरीक़े पर बात कर रहा हूं, जो अब लगभग सौ वर्ष से यहां हैं। इसका तरीक़ा यह है कि विदेश नीति के सभी प्रश्नों और अपनी सेना को प्रभावित करने वाले मामलों को अपने हाथ में रखना। मुझे उम्मीद है कि हम, जो एंपायर की प्रजा हैं, उन मामलों में दख़ल देने की कोशिश नहीं करेंगे जिन्हें सरकार ने अपने पास रखा है। अगर सरकार अफग़ानिस्तान से लड़ती है या बर्मा (म्यांमार) से जीतती है तो उसकी नीति की आलोचना करना हमारा काम नहीं है। इन मामलों को सरकार के हाथ में छोड़े जाने से हमारे हित प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन हम आंतरिक नीति को प्रभावित करने वाले क़ानून से चिंतित है और हमें देखना होगा कि सरकार ने इनसे निपटने का क्या तरीका अपनाया है। सरकार ने लोगों के जीवन संपत्ति और आराम को प्रभावित करने वाले कानून बनाने के लिए एक काउंसिल बनाई है। इस काउंसिल के लिए वह सभी प्रांतों से उन अधिकारियों को चुनती है जो प्रशासन और लोगों की स्थिति से सबसे अच्छी तरह परिचित है।

लोग पूछ सकते हैं कि उन्हें योग्यता के बजाए सामाजिक स्थिति के आधार पर क्यों चुना जाना चाहिए? यह बड़ा दुर्भाग्य है और मैं आपसे यह कहने के लिए क्षमा चाहता हूं कि भारत के जमींदारों के पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है जो उस कुर्सी पर कब्ज़ा करने लायक़ बनाती हो। लेकिन हम उन परिस्थितियों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते जो सरकार को इस नीति को अपनाने के लिए मजबूर करती है। यह ज़रूरी है कि वायसराय की काउंसिल के मेंबर ऊंचे सामाजिक दर्जे के हों।

लोग सोचते हैं कि क़ानून बहुत हो गए हैं और इसकी वजह से मुक़दमे जटिल। जमींदार और काश्तकार के बीच झगड़े पैदा हो गए हैं। उनके विचार बदलने चाहिए। क़ानून ज़्यादा होना देश और उसके लोगों की स्थिति पर निर्भर करता है। नई कंपनियां और इंडस्ट्री सामने आ रही है। नए और अप्रत्याशित कानूनी अधिकार पैदा हुए हैं जो मुस्लिम क़ानून में नहीं दिए गए हैं। जब देश इतनी तेज़ी से बदल रहा है तो यह ज़रूरी है कि नई परिस्थितयों से निपटने के लिए नए क़ानून भी लाए जाएं। सरकार कानूनों की संख्या नहीं बढ़ाना चाहती, पर जब देश की परिस्थितियां बदलती हैं तो यह ज़रूरी हो जाता है कि मुझे नहीं लगता कि क़ौम की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है जिसे सरकार के ध्यान में नहीं लाया जा सकता। हमें अपनी बात कहने से कोई नहीं रोक सकता।

जब भारत सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से महारानी के हाथों में चली गई तो एक क़ानून पारित किया गया जिसमें कहा गया था कि उनके यहां काम करने वाले चाहे गोरे हों या काले, यूरोपीय हों या भारतीय, नियुक्तियों के लिए समान रूप से क़ाबिल होने चाहिए। इसकी पुष्टि महामानी के ऐलान से हुई। हमें देखना है कि सिविल नियुक्तियों में जो नियम बनें, उनमें कोई अपवाद तो नहीं है। क्या हमें किसी ऐसी नियुक्ति से बाहर रखा गया है जिसके लिए हम फिट है, उम्मीदवारों को इंग्लैंड में एक प्रतियोगी परीक्षा देनी होती है। सबके मन में यह ख़्याल आता होगा यह एग्जाम इंग्लैंड में नहीं होना चाहिए। जिस प्रस्ताव को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है, वह यह है कि इसे भारत में आयोजित किया जाए। इसमें एक प्रस्ताव और जोड़ा गया है कि तहसीलदार से लेकर सबोर्डिनेट जज तक के सभी पद भी प्रतियोगी परीक्षा के बाद ही दिए जानें चाहिए।

मैं यह चर्चा नहीं करना चाहता कि इंग्लैंड में प्रतियोगी परीक्षा क्यों आयोजित की जाती है। लेकिन मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि भारत में इस परीक्षा के बाद क्या होगा और देश इसके लिए तैयार है या नहीं? इंग्लैंड में इसका क्या नतीजा होता है? आप जानते हैं कि सभी सामाजिक पदों और निचले रैंक के लोगों को परीक्षा के पास होने की इजाज़त है। सिविल सर्विस के बाद ऊंचे और निचले परिवार के लोग भारत आते हैं। वे भारत के सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। ब्रिटिश जातियों की श्रेष्ठता बनाए रखते हैं। वे सरकार और क़ौम दोनों के लिए अच्छे हैं। लेकिन जो इंग्लैंड से आते हैं, उनके बारे में हमें नहीं पता कि वे लॉर्डस के बेटे हैं या डयूक्स के।

अब सोच कर देखें कि क्या हमारा देश ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार है। यह राजनीतिक अर्थ व्यवस्था का कोई मुश्किल सवाल नहीं है। हर कोई यह समझ सकता है कि किसी भी देश में प्रतियोगी परीक्षा शुरू करने के लिए पहली शर्त है कि उस देश के सभी लोग, चाहे उच्च वर्ग से हों या निचले, सब एक हों। ऐसे देश में कोई मुश्किल पैदा होने की संभावना नहीं है। दूसरा मामला एक ऐसे देश का है जिसमें दो राष्ट्रीयताएं हैं जो इतनी एकजुट हो गई कि व्यावहारिक रूप से एक राष्ट्र हो गईं। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक ऐसा ही उदाहरण है। दोनों देशों में बहुत युद्ध हुए और दोनों ओर से खूब बहादुरी दिखाई गई लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब वे एक जाति के समान हो गए हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है।

बाक़ी पेज 11 पर

उत्तराखंड : सड़कों का जाल पर्यावरण के लिए ख़तरा

उत्तराखंड के चार धामों तक वाहनों के आवागमन की सुविधा को अधिक विस्तार देने के लिए हर मौसम में उपयोग की जा सकने वाली सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसके लिए पहाड़ काटे जा रहे हैं और बड़ी तादाद में वृक्षों का कटान हो रहा है। इस पर पर्यावरणविदों ने गहरी चिंता जताई है। उनका मानना है कि सड़कों को जंगलों, घाटियों, जलधाराओं और आर्द्रभूमि को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है।

सड़क के कारण प्रत्यक्ष निवास स्थान के नुकसान के अलावा जानवरों की प्रजातियों पर इनका असर होता है। इसके अलावा सड़कें जल प्रवाह के प्राकृतिक तरीक़ों को बदल देती हैं, ध्वनि, जल व वायु प्रदूषण को बढ़ाती हैं, अशांति पैदा करती है जो आस-पास की वनस्पतियों की प्रजातियों की संरचना को बदल देती है। पर्यावरण के जानकार मानते हैं कि वायु प्रदूषण की सांद्रता और प्रतिकूल श्वसन स्वास्थ्य प्रभाव सड़क से कुछ दूरी की तुलना में सड़क के निकट अधिक होते हैं। वाहनों से निकलने वाले तत्व सड़क की धूल में मिलकर वायु प्रदूषण की प्रतिक्रिया को और अधिक गतिमान बना देते हैं और मोटर वाहन उत्सर्जन वातावरण में कॉर्बन डाइआक्साइड सांद्रता के विकास और वायुमंडल में गर्मी के बढ़ते प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण कारण हैं। वही, सड़कें जंगली जानवरों की आवाजाही में बाधा बनती हैं। इस वजह से कई वन्य जीव प्रजातियां शिकार के ख़तरे के कारण सड़क पर खुले स्थान को पार नहीं करते हैं और सड़कें यातायात से पशु मृत्यु दर में वृद्धि का कारण बनती हैं। यह बाधा प्रभाव वन्य जीव प्रजातियों को उन क्षेत्रों में प्रवास और पुनःउपननिवेश बनाने से रोक सकता है, जहां वन्य जीव प्रजातियां स्थानीय रूप से विलुप्त हो गई हैं। वन्य जीव विशेषज्ञों का मानना है कि सड़कें पहाड़ों, खेतों और घाटियों में घूमने वाले वन्य जीवों के साथ साथ मानव की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से ख़तरनाक हो सकती हैं, जो वन्यजीवों की मृत्युदर को बढ़ाती है, इससे जड़ी बूटियों के अलावा वन्य जीवों के तेजी से विलुप्त होने का ख़तरा अत्याधिक बढ़ जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय पक्षी विज्ञानी और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग में शिक्षक दिनेश चंद्र भट्ट का मानना है कि हर

बाक़ी पेज 11 पर

क्या कन्हैया और मेवाणी बचाएंगे कांग्रेस?

कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी ने बीते 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हुए, जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप इस्तीफा दिया। जबकि सिद्धू ने कहा कि वह कोई समझौता नहीं करेंगे, नवागंतुक का समग्र संदेश बिल्कुल विपरीत था। 'एक आदमी के चरित्र का पतन समझौता कोने से उपजा, मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब के कल्याण के एजेंडे से कभी समझौता नहीं कर सकता।' कन्हैया और मेवाणी का मामला इसके बिल्कुल उलट था। उनके लिए समझौता पार्टी में शामिल होने का कारण और कांग्रेस को डूबता जहाज बनने से बचाने का एक तरीक़ा था। दोनों सार्वजनिक रूप से झूठ बोल रहे थे कि और कल्पना कर रहे थे कि लोग उनके गेम प्लान के माध्यम से नहीं देखेंगे। सबसे पहले मेवाणी के बारे में क्योंकि वे कांग्रेस में शामिल नहीं हुए लेकिन पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता दी। उनकी धारणा थी कि देश के युवा उनका और कन्हेया का अनुसरण करेंगे। देश के युवा ऐसे लोगों का पक्ष कैसे ले सकते हैं जिनकी पहचान टुकड़े-टुकड़े गैंग और भीमा कोरोगांव की घटना से हुई है, जिसके कारण जातिगत दंगे हुए? ऐसे, अवसरवादियों से देश के युवा कभी मोहित नहीं होंगे।

भीमा कोरेगांव मामले में मेवाणी की भूमिका संदिग्ध है। राजनीतिक दबदबे की कोई भी राशि उन्हें तब तक बरी नहीं करेगी जब तक उन्हें अदालत से मंज़ूरी नहीं मिल जाती। और जो व्यक्ति डॉ. बी.आर. अंबेडकर का अनुयायी होने का दावा करता है, वह उस पार्टी में शामिल हो गया है जिसने बाबा साहेब की राजनीतिक आकांक्षाओं पर रोड़ा अटका दिया था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मेवाणी ने 2017 में गुजरात वे वडगाम विधानसभा सीट एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीती थी, लेकिन उन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। यह कहना ग़लत नहीं होगा कि कांग्रेस ने उनकी उम्मीदवारी को प्रायोजित किया था और यह कहने का क्या शानदार तरीक़ा है कि वह पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस के साथ मंच साझा कर रहे थे और कांग्रेस का समर्थन करेंगे लेकिन तकनीकी कारणों से पार्टी में शामिल नहीं होंगे। वह निश्चित रूप से अगले वर्ष कांग्रेस के टिकट पर गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं।

इस्तीफा देने से एक बेहतर संदेश जाता और आप एक विचार धारा के लिए कम से कम कुछ चीजों का त्याग करने के लिए तैयार हैं और जिस मंच का आप दावा करते हैं वह देश के लिए सही है। ईमानदारी ग़ायब थी नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में असली शक्ति केन्द्र माना जाता था क्योंकि सिद्धू के विद्रोह के कारण चन्नी को नई नौकरी प्राप्त हुई। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की कड़ी आपत्ति न होती तो वे मुख्यमंत्री बन जाते। चन्नी ने कठपुतली नहीं खेलने का या दिखाने का फैसला किया ते वह एक स्टॉप गैप व्यवस्था है। आख़िर वह एक दलित नेता हैं। अहम नियुक्तियों में तमाशा किया गया। सिद्धू जिन्हें पंजाब कांग्रेस का नेतृतव करना था और अभियान में अपने करिश्मे को जोड़ना था, को स्पष्ट रूप से दरकिनार कर दिया गया। इसलिए, इस्तीफा बलिदान नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि अमरिंदर सिंह के बाद उनके अलावा किसी को भी कांग्रेस की विरासत न मिले। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या उन्हें गांधी परिवार के किसी व्यक्ति का समर्थन प्राप्त था। वह इस तरह के समर्थन के बिना एक बिंदु से आगे नहीं जा सकता। फटकार या निलंबन के बजाय जिस तरह से समझौता किया जा रहा है, उससे लगता है कि पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के नेतृत्व में प्रयोग जारी रहेगा। चन्नी और सिद्धू दोनों अब राहुल गांधी की कठपुतली होंगे और वह एक को दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा कर सकते हैं। कन्हैया का मामला हैरान करने वाला है। उन्होंने शहीद भगत सिंह के गुणों की प्रशंसा की, लेकिन एक ऐसी पार्टी में शामिल होने से गुरेज़ नहीं किया जिसका समय कठिन दौर में है। ❑❑

2022 राष्ट्रमंडल खेलों की हॉकी प्रतियोगिता से हटा भारत

भारत कोविड-19 से जुड़ी चिंताओं और देश के यात्रियों के प्रति ब्रिटेन के भेदभावपूर्ण एकांतवास नियमों के कारण अगले वर्ष बमिघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की हॉकी प्रतियोगिता से हट गया। इंग्लैंड भी एक दिन पहले इन्हीं कारणों का हवाला देकर भुवनेश्वर में होने वाले जूनियर पुरुष विश्व कप से नाम वापस ले लिया था।

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोबम ने महासंघ के फैसले से भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा को अवगत करा दिया है। हॉकी इंडिया ने कहा कि बर्मिघम राष्ट्रमंडल खेलों (28 जुलाई से 8 अगस्त) और झांग्झू एशियाई खेलों (10 से 25 सितंबर) के बीच सिर्फ 32 दिन का अंतर है और वे अपने खिलाड़ियों को ब्रिटेन भेजकर जोखिम नहीं उठाना चाहता जो कोरोना वायरस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल रहा है।

निंगोबम ने लिखा कि एशियाई खेल 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए महाद्वीपीय क्वालिफिकेशन प्रतियोगिता है और एशियाई खेलों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए हॉकी इंडिया राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान भारतीय टीमों के किसी खिलाड़ी के कोविड-19 संक्रमित होने का जोखिम नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि इसलिए हॉकी इंडिया अपनी पुरुष और महिला टीमों को राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए नहीं भेजेगा और आपको समय रहते सूचित किया जा रहा है कि आयोजकों को जानकारी दे दी जाए कि वे रिज़र्व टीमों की पहचान करें। कुछ सप्ताह पहले ही इसकी संभावना व्यक्त की जा रही थी जब आइओए अध्यक्ष ने कहा था कि इसकी संभावना व्यक्त की जा रही थी जब आइओए अध्यक्ष ने कहा था कि हॉकी इंडिया ने उन्हें संकेत दिया कि वह एशियाई खेलों के लिए टीम को शीर्ष फार्म में रखना चाहती है चूंकि यह ओलंपिक क्वालिफायर भी है।

खेल मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि हॉकी इंडिया को इस बात के लिए मनाने की कोशिश की जाएगी कि वहां दूसरे दर्जे की टीम भेज दे। ब्रिटेन ने हाल में भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों को मान्यता देने से इंकार कर दिया था और देश से आने वाले यात्रियों के पूर्ण टीकाकरण के बावजूद उनके लिए 10 दिन का कड़ा एकांतवास अनिवार्य किया है। आइओए अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में निंगोबम ने इस भेदभाव का प्रमुखता से ज़िक्र किया है उन्होंने रिजर्व टीमों के लिए खेल की वैश्विक संचालन संस्था के साथ समन्वय के निर्देश दिए हैं। बत्रा एफआइएच के भी अध्यक्ष हैं। निंगोबम ने लिखा है कि इस तरह की भेदभावपूर्ण पाबंदियां भारतीय खिलाड़ियों और अधिकारियों पर हाल में हुए तोक्यो ओलंपिक खेलों के दौरान भी लागू नहीं थी और टीकाकरण

बाक़ी पेज 11 पर

नाम्या को चैंपियन बनाने में कोच व मामा की अहम भूमिका

मात्र 14 वर्ष की आयु में पेरू में जूनियर विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण जीतकर सबको चौंकाने वाली नाम्या कपूर ने अपने मामा और तीन बार के ओलंपियन संजीव राजपूत की राह पर चलना शुरू कर दिया है। नाम्या अपने मामा के साथ बड़ी बहन खुशी से भी प्रेरणा लेती है। खुशी निशानेबाज़ी राष्ट्रीय टीम में चयन का दरवाज़ा खटखटा रही हैं।

परिवार में निशानेबाज़ों की मौजूदगी के अलावा घर से बाहर उनका ख़्याल 'समर्पित' कोच अंकित शर्मा रखते हैं। नाम्या पिछले कुछ साल से फरीदाबाद स्थित अंकित की अकादमी में प्रशिक्षण ले रही हैं।

नाम्या ने हमवतन स्टार निशानेबाज़ मनु भाकर को पीछे छोड़कर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इससे वह 14 वर्ष की आयु में शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली सबसे कम आयु की भारतीय निशानेबाज़ बन गईं। नाम्या फाइनल में 36 अंग बनाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। वह फ्रांस की कैमिली जेद्राजेवस्की (33) और 19 वर्षीय ओलंपियन भाकर (31) से आगे रहीं।

कपूर परिवार अपनी सबसे छोटी बेटी के शानदार कारनामे से बहुत खुश है लेकिन हैरान नहीं है। उनकी मां गुंजन ने कहा कि हमें नाम्या और खुशी से उम्मीदें हैं क्योंकि दोनों निशानेबाज़ी में काफी मेहनत करती हैं और प्रतिभाशाली भी हैं। गुंजन ने अपनी दोनों बेटियों के विकास और सफलता का श्रेय अंकित को दिया।

उन्होंने कहा कि अंकित ने निशानेबाज़ के रूप में उनके विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस तरह से उन्होंने काम किया है उससे वह विश्व चैम्पियनशिप में नाम्या के स्वर्ण पदक के लिए हर श्रेय के हक़दार हैं। अंकित ने हालांकि श्रेय लेने से बचते हुए कहा कि नाम्या में शानदार निशानेबाज़ बनने की काफी संभावनाएं हैं। अंकित की इस बात से राजपूत भी सहमत दिखे। राजपूत ने कहा कि नाम्या और खुशी में प्रतिभा है और वे देश के लिए बड़ी संभावनाएं हैं सिर्फ निशानेबाज़ी में ही नहीं, वे पढ़ाई में भी तेज़ हैं। राजपूत ने कहा कि दोनों के साथ उनके कोच काम कर रहे हैं, जब भी हम पारिवारिक समारोहों के दौरान मिलते हैं तो मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूं। ज़्यादातर मौक़ों पर मैं उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश करता हूं और इस खेल की सामग्री मुहैया कराकर मदद करता हूं। अंकित ने कहा कि संजीव भाई की सलाह से काफी मदद मिलती है। परिवार की भूमिका काफी अहम हो जाती है। ❑❑

जानलेवा दिमाग़ी दौरा

मस्तिष्क की लाखों कोशिकाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए कई कोशिकाएं हृदय से मस्तिष्क तक लगातार रक्त पहुंचाती रहती हैं। जब रक्त आपूर्ति बाधित हो जाती है, तब मस्तिष्क की कोशिकाएं मृत होने लगती है। इसका परिणाम होता हे दिमागी दौरा या ब्रेन स्ट्रीक। यह मस्तिष्क में ब्लड क्लॉट बनने या ब्लीडिंग होने से भी हो सकता हैं। रक्त संचरण में रुकावट आने से कुछ ही समय में मस्तिष्क की कोशिकाएं मृत होने लगती है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति रुक जाती है। जब मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली नलिकाएं फट जाती है तो इसे ब्रेन हैमरेज कहते हैं। इस कारण पक्षाघात होना, याददाश्त जाने की समस्या, बोलने में असमर्थता जैसी स्थिति आ सकती है। कई बार यह जानलेवा भी हो सकता है। इसे ब्रेन अटैक भी कहते हैं।

लक्षण

अलग अलग लोगों लक्षण होते हैं। कई मामलों में तो मरीज़ को पता ही नहीं चलता कि वह ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हुआ हैं इन्हीं लक्षणों के आधार पर डाक्टर पता लगाते हैं कि स्ट्रोक के कारण मस्तिष्क का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। अकसर लक्षण अचानक दिखाई देते हैं।

अचानक संवेदनशून्य हो जाना या चेहरे, हाथ या पैर में, विशेष रूप से शरीर के एक भाग में कमज़ोरी आ जाना।

मांसपेशियों का विकृत हो जाना।

समझने या बोलने में दिक्क़त होना।

एक या दोनों आंखों की क्षमता प्रभवित होना।

अचानक गंभीर सिरदर्द होना।

किन्हें है अधिक ख़तरा

टाइप-2 डायबिटीज के मरीज़ों में खतरा बढ़ जाता है।

हाई बीपी और हाइपरटेशन के मरीज़ इसकी चपेट में जल्दी आ जाते हैं।

धूम्रपान, शराब और गर्भ निरोधक गोलियां ब्रेन अटैक को निमंत्रण देने वाले कारण माने जाते हैं।

कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता स्तर, घटती शारीरिक सक्रियता भी कारण बन सकती है।

कारण को जानें

मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली नलिकाओं के क्षतिग्रस्त होने के कारण या उनके फट जाने के कारण ब्रेन अटैक होता है। इन नलिकाओं के क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण आर्टियोस्क्लेरोसिस है। इसके कारण नलिकाओं की दीवारों में वसा, संयोजी ऊतकों, क्लॉट, कैल्शियम या अन्य पदार्थों का जमाव हो जाता है। इस कारण नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे उनके द्वारा होने वाले रक्त संचरण में रुकावट आती है या नलिकाओं की दीवार कमज़ोर हो जाती है।

क्या है उपचार

ब्रेन स्ट्रोक के शुरुआती लक्षणों को टीआईए (ट्रांजेंट इस्किकि अटैक) कहा जाता है। ये लक्षण अस्थायी या कम समय के लिए होते हैं, लेकिन लापरवाही से स्थिति गंभीर हो सकती है। अगर तीन घंटे के भीतर मरीज़ का इलाज शुरू हो जाए तो दवाओं से क्लॉटिंग खत्म की जा सकती है। ऐसे मरीज़ों को खून के थक्के गलाने वाला इंजेक्शन दिया जाता है। इससे थक्का बनने की प्रक्रिया रुक जाती है। प्राथमिक स्तर पर इसके उपचार में रक्त संचरण को सुचारु और सामान्य करने की कोशिश की जाती है, ताकि मस्तिष्क की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। कई अस्पतालों में थ्रोम्बोलिसिस के अलावा एक और उपचार उपलब्ध है, जिसे सोनो थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। यह मस्तिष्क में मौजूद ब्लड क्लॉट को नष्ट करने का एक अल्ट्रा साउंड तरीका है। इसमें केवल दो घंटे लगते हैं। इसलिए स्ट्रोक अटैक के तीन घंटे के भीतर जो उपचार उपलब्ध कराया जाता है, उसे गोल्डन पीरियड कहते हैं।

लाएं सकारात्मक बदलाव

तनाव न लें, मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाएं।

नियमित रूप से व्यायाम और योग करें।

अपना भार औसत से अधिक न बढ़ने दें।

सोडियम का अधिक मात्रा में इस्तेमाल न करें।

गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन न करें, परिवार नियोजन के दूसरे तरीके अपनाएं।

पौष्टिक भोजन भी है कारगर

बाक़ी पेज 11 पर

शेष.... प्रथम पृष्ठ

क्षेत्र था स्वास्थ्य।

अमूमन आम दिनों में आबादी के छोटे हिस्से से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का संपर्क होता है और उनका अनुभव कोई बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन इस बार तो महामारी के चलते बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी अस्पतालों का रुख़ करना पड़ा और बड़े पैमाने पर उन्हें ऐसे अनुभवों से गुज़रना पड़ा, जो प्रचलित क़ानूनों के अंतर्गत भी भ्रष्टाचार की परिधि में आते हैं और इन मामलों में मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे। देशभर के अख़बार ऐसी ख़बरों से भरे पड़े थे, जिनमें मरीज़ों या तीमारदारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, दवाओं और अन्य सुविधाओं के लिए अवैध उगाही या फिर सरकारी तंत्र की अक्षमता के क़िस्से बयान किए गए थे। महामारी के दौरान जनता को मिले कटु अनुभवों पर गीत रचे गए, कहानियां लिखी गईं, फिल्में बनीं और इन सबके बावजूद ब्यूरो की रिपोर्ट अगर भ्रष्टाचार के मामले कम दिखा रही है, तो स्पष्ट है कि इसे गहराई से परखने की ज़रूरत है। पूरी संभावना है कि बहुत कम प्रकरण थानों में लिखे गए। यह भी संभव है कि बहुत से मामलों में पीड़ित पुलिस के पास न गए हों। लोगों को उम्मीद नहीं रहती कि उनकी शिकायतें दर्ज होंगी या वे सरकारी मशीनरल से ऐसे ही व्यवहार की उम्मीद करते हों और जब तक कोई बड़ी दुर्घटना न घटे, वे थाना कचहरी के चक्करे में नहीं पड़ना चाहते।❑❑

शेष.... हरियाणा और पंजाब...

है। यह टीम सर्दियों के पूरे सीजन में 24 घंटे सातों दिन काम करेगी।

प्रश्नः- प्रदूषण नियंत्रण में सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं..?

उत्तरः- जब हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो दिल्ली की भौगोलिक बनावट को भी अनदेखा नहीं कर सकते। 300 किमी के दायरे में दिल्ली की स्थिति ढलान वाली है। इसीलिए उत्तर भारत के इलाक़ों में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, एयर शेड की वजह से उन सबका सबसे ज़्यादा प्रभाव दिल्ली पर ही पड़ता है। हालांकि दिल्ली के वायु प्रदूषण में दिल्ली की भी हिस्सेदारी होती है, लेकिन यहां प्रदूषण स्तर बढ़ने का कारण बाहर से आने वाला प्रदूषण होता है इसलिए प्रदूषण से जंग में दिल्ली एनसीआर की एकीकृत कार्य योजना होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अवधारणा भी यही है। अगर एक जगह गतिविधियों पर रोक है और दूसरी जगह वो सभी चल रहीं हैं तो फिर उसके अपेक्षित परिणाम आ ही नहीं पाएंगे।❑❑

शेष.... पूरी पीढ़ी पर छाता....

सामाजिक वर्गीकरण किया था, जिसके मुताबिक, मरने वालों में 61 प्रतिशत से ज़्यादा निर्बल आय और सामाजिक वर्ग के लोग थे। मरने वालों के पास खुद को क्वारंटीन करने लायक़ घर की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए महामारी ने उन पर समूचि उग्रता से झपट्टा मारा। महामारियां कमज़ोर वर्ग को ज़्यादा निशाना बनाती है। दुर्भाग्य से इस बार भी ऐसा ही रहा है।❑❑

शेष.... हमारी कौम और देश....

अकेले हिंदुओं पर विचार करें। हमारे प्रांत के हिंदू, पूर्व के बंगाली और दक्खन के मराठा एक राष्ट्र नहीं बनाते हैं। अगर आपकी राय में भारत के लोग एक राष्ट्र बनाते हैं तो बेशक प्रतियोगी परीक्षा शुरू की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है तो देश प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार नहीं है। तीसरा, यह मामला एक ऐसे देश का है जिसमें कई राष्ट्रीयताएं हैं, जो एक-दूसरे के मुक़ाबले में बराबरी पर हैं। चाहे वे इसका फायदा उठाएं या नहीं। क्या मुसलमानों ने हायर अंग्रेजी एजूकेशन के बारे में यह स्थिति प्राप्त कर ली है? जो उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए ज़रूरी है जिससे उन्हें हिन्दुओं के स्तर पर रखा जा सके? निश्चित रूप से नहीं क्या हमारे प्रांत के मुसलमान और हिन्दू बंगालियों से बराबरी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब ऐसा है तो हमारे देश में प्रतियोगी परीक्षा कैसे शुरू की जा सकती है।

मेरे दोस्त बाद में यह न कहें कि मैंने उन्हें बताया नहीं कि हमारी क़ौम और देश का फायदा कहां हैं। मेरी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, हालांकि मैं अपने राष्ट्र को उस मुक़ाम पर तक पहुंचते देखने के लिए जीवित नहीं रह सकता हूं जैसा मेरा दिल चाहता है। फिर भी जो लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं वे निश्चित रूप से देश को ऐसा सम्मान, समृद्धि और ऊंचा दर्जा दिलवाते हुए देखेंगे। (कोलंबिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से साभार)❑❑

शेष.... जान न ले ले दिमाग़ी दौरा

साबुत अनाज खाएं क्योंकि ये फाइबर के अच्छे स्रोत होते हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में सहयोग करते हैं।

अदरक का सेवन करें, क्योंकि इससे रक्त पतला होता है और थक्का बनने की आशंका कम हो जाती है।

ओमेगा फैटी एसिड वाले खाद्य पदार्थ जैसे तैलीय मछलियां अखरोट, सोयाबीन आदि अपने खाने में शामिल करें। ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं, जिससे खून जमने का खतरा भी कम हो जाता है।

जामुन, गाजर, टमाटर और गहरी हरी पत्तेदार सब्ज़ियां ज़रूर खाएं, क्योंकि इनमें एंटी ऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत होती है।

गर्म और ताज़ा भोजन खाएं, जिसमें सैचुरेटेड वसा और नमक की मात्रा कम हो।❑❑

ममता देंगी सपा का साथ!

मोदी के ख़िलाफ़ नेतृत्व के प्रश्न पर ममता और कांग्रेस के बीच बढ़ती दूरी की एक वजह यूपी चुनाव भी बन सकता है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि ममता को यूपी चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के मंच पर देखा जा सकता है। बंगाल चुनाव के मौक़े पर अखिलेश यादव ने बंगाल में रहने वाले यूपी मूल के निवासियों से ममता को वोट देने की अपील की थी। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बंगाल की वामगठबंधन सरकार में मंत्री रह चुके किरणमय नंदा स्थानीय स्तर पर ममता के साथ मंच साझा करते रहे हैं। अब जबकि यूपी के चुनाव होने हैं, ममता के लिए यह तय करना बाकी है कि वहां उनकी क्या भूमिका होगी? एक रास्ता यह हो सकता था कि किसी भी पार्टी काा नाम लिए बग़ैर वह भाजपा को हराने की अपील कर दें, लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि इससे उनको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने ममता के साथ एक मध्यस्थ के ज़रिए जो बातचीत शुरू कराई है, उसमें उनका आग्रह यही हे कि 'दीदी' को उनका खुलकर साथ देना चाहिए। एसपी खेमे से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को भी यह यकीन है कि यूपी में अगर भाजपा को कोई हरा सकता है कि तो वह है सपा। इसलिए वह खुलकर अखिलेश यादव की पार्टी का समर्थन कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो यह बात कांग्रेस को पसंद आने वाली नहीं है क्योंकि वह यूपी में अपनी वापसी के लिए पूरा ज़ोर लगाए हुए है। 2017 के चुनाव में तो एसपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था, लेकिन इस बार वह ऐसे गठबंधन के लिए किसी भी सूरत में राज़ी नहीं है। उधर, आम आदमी पार्टी को लेकर एसपी का रुख़ नरम है। वह शहरी इलाक़े की कुछ सीटें 'आप' के लिए छोड़कर अरविंद केजरीवाल से समर्थन ले सकती है।

शेष.... मंज़र पस-मंज़र

में लाने पर कोई सहमति नहीं बनती दिखना भी बता रहा है कि भविष्य में पेट्रोलियम उत्पाद महंगे ही होंगे। यानि हर तरह से महंगाई बढ़ेगी। वित्त मंत्री कह चुकी हैं कि पेट्रोल और डीजल पर शुल्क में कोई कटौती नहीं होगी और महंगाई से केन्द्र व राज्यों को मिल कर निपटना है। इस वक्त बड़ी दिक्क़त यह है कि महामारी ने लोगों की माली हालत खस्ता कर बिगाड़ रखी है, रोज़गार भी नहीं है उस यह व्यवस्था। आमद गिर रही है। ऐसे में लोग कैसे जी पाएंगे महंगाई बेक़ाबू होकर ग़रीबों को मरने के लिए मजबूर करने लगे, इससे पहले केन्द्र और राज्यों को उन तात्कालिक और दूरगामी उपायों के बारे में सोचना चाहिए जो आम आदमी को इससे बचा सकें।❑❑

'असम मॉडल' का ख़ौफ़

भाजपा शासित राज्यों में 'असम मॉडल' का ख़ौफ़ सिर चढ़ कर बोल रहा है, विशेषकर उन पांच में से चार राज्यों में, जहां कुछ माह के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। दरअसल, असम में पिछले चुनाव के मोक़े पर वहां भाजपा की सरकार होने के बावजूद पार्टी आलाकमान ने उस समय के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को अगले चुनाव के लिए सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था। टीम चुनाव लड़ेगी, यह कहते हुए पार्टी चुनाव के मैदान में गई थी और बहुमत मिलने पर उसने मुख्यमंत्री बदल दिया। तर्क दिया कि विधायकों ने अपनी पसंद का सीएम चुना है। जिन पांच राज्यों में अगले कुछ माह में चुनाव होने हैं, उनमें पंजाब को छोड़कर बाकी चार राज्यों में भाजपा की ही सरकार है और अभी तक इनमें से किसी भी राज्य में औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है कि पार्टी किसे मुख्यमंत्री प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतरेगी। जहां सीएम होता है, उसका चेहरा तो स्वाभाविक रूप से माना जाता है लेकिन असम में जो कुछ हुआ, उसके बाद यह बात बेमानी हो गई। इसी को 'असम मॉडल' कहा जा रहा है और वही ख़ौफ बाकी राज्यों के सीएम पर बना हुआ है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं का नज़रिया है कि 'असम मॉडल' को कई दूसरे राज्यों में अपनाया जा सकता है। पार्टी के एक सीनियर लीडर का बयान भी आया है कि भाजपा डेमोक्रेटिक पार्टी है और उसके यहां सभी फैसले डेमोक्रेटिक तरीके से होते हैं। इससे तो यही संकेत मिलता है कि नतीजों के बाद विधायकों को अपना नेता चुनने का अधिकार होगा।

शेष.... उत्तराखंड : सड़कों का जाल...

मौसम में उपयोग आने वाली सड़कों में क्योंकि चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसलिए पहाड़ों का कटान अधिक होता है। कटान के मलबे को पास के गधेरों और पर्वतीय नदियों में डाला जाता है जिससे प्रकृति के पारिस्थितिकी व्यवस्था में तेज़ी से बदलाव आता है और स्थानीय स्तर पर वनस्पति और जीव जंतुओं के अंडे, चूजे, बच्चों को अत्याधिक हानि होती है। इसमें कई दुर्लभ प्रजातियों के जीव जंतुओं के विलुप्त होने का ख़तरा होता है। उत्तराखंड के चार धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री के लिए सड़कों के जाल बिछाने के नाम पर जिस तरह पहाड़ों का दोहन हो रहा है, उससे इस बार मानसून के दौरान पहाड़ में काफी तबाही हुई है। उत्तराखंड के सीमांत पर्वतीय जिले उत्तरकाशी के बड़ेथी में हर मौसम सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था जिससे करीब आधा दर्जन मकान ख़तरे की जद में आ गए। इस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी प्रश्न उठाए हैं। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी पहाड़ के कटान के कारण कई गांव तबाही की चपेट में आए। उत्तराखंड की हर मौसम में उपयोग में आने वाली सड़कों के ख़िलाफ़ कई पर्यावरणविदों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया था कि हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कों के निर्माण में सड़क परिवहन मंत्रालय के 2018 के शासनादेश को ही लागू किया जाए। केन्द्र सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह बात रखी गई कि 'हर मौसम सड़क' परियोजना के तहत चीन से जुड़े सीमा क्षेत्र तक भी सड़क पहुंचनी है। ऐसे में सेना के वाहन भी इस सड़क से होकर गुज़रेंगे, इसलिए इस परियोजना के तहत सड़कों की चौड़ाई पांच मीटर से बढ़ाकर सात मीटर रखी जाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिसंबर 2016 में इस परियोजना की देहरादून के परेड मैदान में एक जनसभा के दौरान नींव रखी थी। 11,700 करोड़ की इस परियोजना द्वारा उत्तराखंड स्थित चारों धामों को 12 महीने सहूलियत वाली सड़कों से जोड़ा जाना है।❑❑

शेष.... 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की....

करवाने वाले खिलाड़ियों के लिए भी 10 दिन के एकांतवास से उनका प्रदर्शन प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि ये पाबंदियां भारत के ख़िलाफ़ भेदभावपूर्ण हैं और काफी दुर्भाग्यशाली हैं। इंग्लैंड के कोविड-19 से जुड़ी चिंताओं और भारत सरकार के ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए 10 दिन का एकांतवास अनिवार्य करने का हवाला देकर भुवनेश्वर में अगले माह होने वाले एफआइएच पुरुष जूनियर विश्व कप से हटने के एक दिन बाद हॉकी इंडिया ने यह क़दम उठाया है। ब्रिटेन की पाबंदियों के बाद भारत ने भी देश में आने वाले ब्रिटेन की नागरिकों पर उसी तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। भारत के नए नियमों के तहत ब्रिटेन से यहां आने वाले ब्रिटेन के सभी नागरिकों चाहे उनके टीकाकरण की स्थिति कुछ भी हो उन्हें यत्रा के 72 घंटे के भीतर आरटी- पीसीआर परीक्षण का नतीजा दिखाना होगा। भारत पहुंचने पर हवाई अड्डे में और आठवें दिन उनके दो और आरटी-पीसीआर परीक्षण होंगे। भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों के पदक दौर में पहुंची थी लेकिन कांस्य पदक के प्लेऑफ में इंग्लैंड से हार गई थी। पुरुष टीम को 1-2 जबकि महिला टीम को 0-6 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी।❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **17 Oct.2021** Posting Days : **MON. - TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

घायलों की मदद के लिए केन्द्र सरकार का बड़ा फैसला

•सर्दी आगमन पर अमल ज़रूरी•महंगाई का कोड़ा

घायलों की मदद के लिए केन्द्र सरकार का बड़ा फैसला

अक्सर सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को दूसरे लोग पुलिस के डर से अस्पताल नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे में बिना इलाज के उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अब सरकार लोगों के मन से ये डर निकालकर उन्हें ऐसे लोगों की मदद के लिए प्रेरित कर रही है। इसके तहत सड़क मंत्रालय ने कहा कि उसने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को गंभीर चोट लगने के एक घंटे भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगारों के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उन्हें 5,000 रुपये का नक़द पुरस्कार दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों के प्रधान सचिवों और परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि यह योजना 15 अक्तूबर 2021 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी होगी। मंत्रालय ने नेक मददगार को पुरस्कार देने को योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का मक़सद आपातकालीन स्थिति सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए आम जनता को प्रेरित करना है। नक़द पुरस्कार के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर 10 सबसे नेक मददगारों को एक-एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। मंत्रालय की ओर से एक वेब पोर्टल भी शुरू किया गया है। इसमें ज़िला प्रशासन की ओर से हर माह घायलों की मदद करने वालों की पूरी जानकारी अपलोड की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस और अस्पताल प्रशासन भी इस जानकारी को अपलोड कर सकेंगे। सडञ्क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से घायलों की मदद करने वाले लोगों को पहले ही पुलिस की कार्यवाही से बचने की छूट दी हुई है। इसके अनुसार पुलिस और अस्पताल प्रशासन ऐसे लोगों पर उनकी पहचान, पता अन्य जानकारी देने का दबाव नहीं डाल सकते। इसके साथ ही पुलिस उन्हें थाने में नहीं बुला सकती। वही उन्हें किसी मामले में गवाही बना सकती हैं केन्द्र सरकार के इस फैसले से निश्चित ही सुनसान जगहों पर सड़क हादसों के शिकार हुए लोगों को मदद मिलेगी। सरकार का यह फैसला क़ाबिले तारीफ है। बहरहाल, देखना यह है कि इस योजना से आम लोगों को कितना लाभ मिलता है।

सर्दी आगमन पर अमल ज़रूरी

राजधानी में सर्दी के दिनों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। इस योजना में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के चौतरफा उपाए किए गए हैं, जो स्वागतयोग्य है। विंटर एक्शन प्लान में धूल फैलने और कूड़ा जलाने से रोकने की निगरानी पर ख़ासा ज़ोर दिया गया है, जिसके लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। पराली प्रबंधन के लिए संयुक्त हार्वेस्टर और बायो-डी कंपोजर के इस्तेमाल की बात की गई है, वहीं हाट स्पॉट क्षेत्रों की नए सिरे से पहचान कर विशेष टीमों के जरिये वहां निगरानी करने की योजना है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यातायात जाम वाली सड़कों की पहचान करने के साथ ही तय समय सीमा वाली पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप करने व वाहनों की प्रदूषण जांच की व्यवस्था में भी तेज़ी लाने की योजना है।

एक योजना के तौर पर निश्चित ही यह प्रभावी नज़र आती है। ऐसी उम्मीद भी की जानी चाहिए कि दिल्ली सरकार इस योजना पर पूरी तरह अमल करेगी और यह ज़मीन पर अपना प्रभाव छोड़ेगी। लेकिन, जैसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

सऊदी अरब ने रसोई गैस के दाम पिछले तीन महीने में तीन सौ चौदह डॉलर प्रति टन तक बढ़ा दिए हैं, चूंकि भारत तेल और गैस का आयात करता है, इसलिए इन उत्पादों के महंगा होने का तर्क दिया जा सकता है लेकिन प्रश्न यह है कि आख़िर इन दामों को बढ़ाने की कोई सीमा है या नहीं?

ने कहा, दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्लीवासियों को भी आगे आना होगा, तभी यह योजना सही मायने में सफल हो पाएगी। दिल्लीवासियों को भी प्रदूषण की चिंता करते हुए निर्माण स्थलों इत्यादि पर धूल फैलने से रोकने के पुख़्ता उपाय करने होंगे। यही नहीं, कूड़ा जलाने से रोकने में भी आम जनता का योगदान काफी अहम साबित हो सकता है। जहां तक संभव हो सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करने और निजी वाहनों का प्रयोग कम करने से ईंधन जलने से होने वाले प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके एक्शन प्लान पर धरातल पर पूरी ईमानदारी से काम हो।

महंगाई का कोड़ा

पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दाम आम आदमी पर लगातार बोझ बढ़ा रहे हें। इस वर्ष जनवरी से हर महीने पच्चीस-पच्चीस रुपए करके रसोई गैस के दाम बढ़ा जाते रहे हैं। अब फिर पन्द्रह रुपए बढ़ा दिए। पांच किलो वाला सिलेंडर पांच सौ के पार चला गया है। चाहे सब्सिडी वाला सिलेंडर हो या बिना सब्सिडी वाला या फिर व्यावसायिक इस्तेमाल वाला सिलेंडर, सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल और डीजल तो पहले ही से लगातार महंगा होता जा रहा है। चिंता की बात ज़्यादा इसलिए भी है कि इन उत्पादों की महंगाई नित नए कीर्तिमान बना रही है। दाम वृद्धि के इस रुख़ से साफ है कि आने वाले दिनों में कोई राहत मिलने की बात तो दूर, बल्कि और महंगाई के लिए तैयार रहना होगा। सरकार साफ कह चुकी है कि इन बढ़ते दामों को रोक पाना फिलहाल संभव नहीं है। ज़ाहिर है, महंगाई अभी पीछा नहीं छोड़ने वाली।

पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने के पीछे तात्कालिक वजह अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ना बताई जा रही है। विदेशी बाज़ार में कच्चा तेल सात साल के उच्चतम स्तर पर चल रहा है। सऊदी अरब ने रसोई गैस के दाम पिछले तीन महीने में तीन सौ चौदह डॉलर प्रति टन तक बढ़ा दिए हैं, चूंकि भारत तेल और गैस का आयात करता है, इसलिए इन उत्पादों के महंगा होने का तर्क दिया जा सकता है लेकिन प्रश्न यह है कि आख़िर इन दामों को बढ़ाने की कोई सीमा है या नहीं? यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की अधिकांश आबादी रसोई गैस का ही उपयोग करती है। इनमें बेहद गरीब परिवारों की संख्या भी करोड़ों में ही है, ऐसे में लोग कैसे नौ सौ या हज़ार का सिलेंडर खरीद पाएंगे? जिस तेजी से रसोई के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उससे तो लगता है कि जल्दी ही यह आंकड़ा डेढ़ हजार को छू जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

यह सही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में रसोई गैस और कच्चे तेल के दामों को नियंत्रित कर पाना सरकार के दायरे के बाहर है लेकिन देश के भीतर लोगों को उचित दाम पर ये चीज़ें कैसे मिलें, इसके उपाय तो किए ही जा सकते हैं। पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाने वाले भारी भरकम शुल्कों को लेकर लंबे समय से आवाज़ उठती रही है। एक लीटर पेट्रोल या डीजल के दाम में दो तिहाई के करीब तो केन्द्र और राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क ही होते हैं। सरकारों ने इसे खज़ाना भरने का बड़ा ज़रिया बना लिया है। दरअसल सरकारें जानती हैं कि ईंधन, रसोई गेस, दूध और खाने पीने की कितनी भी महंगी क्यों न कर दी जाए लोग बिना खरीदे यह नहीं रह सकते। पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे

बाक़ी पेज 11 पर

मामा की राह पर तेज प्रताप?

बिहार में लालू परिवार के बीच राजनीतिक विरासत का झगड़ा सामने आ गया है। पहले तेजस्वी के ख़िलाफ़ सांकेतिक लड़ाई लड़ रहे तेज प्रताप अब खुलकर उनके विरोध में आ खड़े हुए हैं और उपचुनाव के बहाने दोनों भाईयों के बीच पाले भी बंट गए हैं। तेज प्रताप ने आरजेडी से हटकर अपनी ताक़त दिखाने को अपना एक संगठन भी बनाया हुआ है। वहीं हो रहे उपचुनाव में एक सीट पर आरजेडी के मुक़ाले कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा से यह चर्चा तेज़ हो गई है कि क्या तेज प्रताप भी अपने मामा साधु यादव की राह पर जा रहे हैं। एक वक़्त साधु यादव का बिहार में ख़ौफ देखने लायक़ था। यह वह दौर था जब लालू और उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थीं। वह किसी पद पर न होते हुए भी सुपर सीएम कहे जाते थे। चूंकि उस वक़्त तेज प्रताप और तेजस्वी राजनीति में नहीं थे, इसलिए ले-देकर परिवार की नुमाइंदगी साधु यादव के हाथ में हुआ करती थी। बाद में जब लालू यादव को अहसास हुआ कि साधु यादव के ज़रिए पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है तो उन्होंने उन्हें किनारे लगाना शुरू किया। यहीं से दोनों परिवारों में मनमुटाव की शुरुआत हुई और फिर उन्होंने अपना अलग राजनीतिक रास्ता चुन लिया। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, वह कांग्रेस में भी रहे, उन्होंने आरजेडी को ख़त्म करने की क़सम भी खाई, लेकिन सफल नहीं हुए। एक बार साधु यादव को लेकर लालू से प्रश्न हुआ तो उन्होंने पलटकर प्रश्न पूछ लिया था कि कौन साधु? देखना दिलचस्प होगा कि तेज प्रताप का आगे का सफर कैसा होता है।

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर
SHANTI MISSION
❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in —— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक शकील अहमद सैयद ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173